राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

स्वतंत्र प्रभात

@swatantraprabhatmedia @swatantramedia RNI.No. UHIN/2012/43078 (epaper.swatantraprabhat.com) @SwatantraPrabhatonline news@swatantraprabhat.com

सीतापुर से प्रकाशित एंव अयोध्या ,प्रयागराज ,मिर्जापर ,गोरखपुर , बरेली ,बुंदेलखंड , उत्तराखंड , देहरादून

सीतापुर, शुक्रवार, 09 जनवरी 2026

वर्ष 14,अंक 266, पृष्ट 04, मूल्यः 01 रुपया

www.swatantraprabhat.com

गाज़ियाबाद , दिल्ली , हरियाणा , चंडीगढ़ , झारखण्ड , बिहार , मध्य प्रदेश ,असम, तेलंगाना आदि जनपदो में प्रसारित

स्वतंत्र प्रभात दैनिक अख़बार तथा ऑनलाइन चैनल से सीधा जुड़ने के लिए संपर्क करें.....
9511151254

ग्राम पंचायत गुरेरा में दबंगों ने बंजर भूमि और चक मार्ग पर किया कब्जा..03

बुढार स्टेडियम में सजेगा क्रिकेट का महाकुंभ..04

वैष्णोदेवी मेडिकल कॉलेज: एमबीबीएस अनुमति रद्द होने पर राजनीतिक दल बोले- शिक्षा का सांप्रदायिकीकरण

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली- राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने जम्मू-कश्मीर के श्री माता वैष्णो देवी (एसएमवीडी) इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस को एमबीबीएस पाठ्यक्रम में दाख़िले की पिछले साल सितंबर में दी गई अनुमति को वापस लेने के बाद तीखी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई हैं. मालूम हो कि एनएमसी ने 'न्यूनतम मानकों के पालन में गंभीर खामियों' का हवाला देते हुए एसएमवीडी विश्वविद्यालय को जारी 'लेटर ऑफ परमिशन' (एलओपी) वापस ले ली है. विश्वविद्यालय का बोर्ड ही इस मेडिकल संस्थान का संचालन करता है. गौरतलब है कि पिछले साल नीट रैंकिंग के आधार पर पहले बैच में दाख़िला पाने वाले 50 छात्रों में से 47 मुस्लिम, एक सिख और केवल दो हिंदू थे. जिसके बाद हिंदुत्व संगठनों और भाजपा के नेताओं ने मेरिट लिस्ट का विरोध करना शुरू कर दिया था. वे यह कहते हुए संस्थान बंद करने की मांग कर रहे थे कि इसे 'हिंदू तीर्थयात्रियों के दान' से चलाया जा रहा है इसलिए यहां एमबीबीएस सीटें केवल हिंदू छात्रों के लिए आरक्षित होनी चाहिए।

राजनीतिक प्रतिक्रियाएं

एनएमसी के इस इस कदम पर तीखी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं. जम्मू-कश्मीर के नेताओं ने इसे शिक्षा का 'सांप्रदायिकीकरण' कहा है. जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ़्ती ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि यह फैसला शिक्षा के 'सांप्रदायिकीकरण के नुकसानदेह नतीजों' को साफ़ तौर पर उजागर करता है. उन्होंने कहा, 'बीमारी का इलाज करने के बजाय बिना किसी गलती के मरीज़ को ही सज़ा दी जा रही है.' मुफ़्ती ने आगे कहा कि इससे भी ज़्यादा चिंताजनक यह है कि अगर 'एसएमवीडी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के साथ ऐसा किया जा सकता है, तो इसे कहीं और भी दोहराया जा सकता है, जिससे मेहनती युवाओं का भविष्य गंभीर ख़तरे में पड़ सकता है.' उन्होंने कहा, 'यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब भाजपा धार्मिक आधार पर दाख़िले सीमित करने की बात कर रही है, जो इसे और भी ख़तरनाक बनाता है. दुर्भाग्य से, हमारे मुख्यमंत्री भी इस फैसले के साथ खड़े नज़र आते हैं, जो गंभीर संदेह और चिंता पैदा करता है।'

हालांकि, जम्मू कश्मीर के मुख्तमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी इस कदम की कड़ी आलोचना की है. उन्होंने कहा, 'देश के अन्य हिस्सों में लोग अपने इलाके में मेडिकल कॉलेज लाने के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन यहां मेडिकल कॉलेज बंद कराने के लिए लड़ाई लड़ी गई.' सांबा में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, 'आपने जम्मू-कश्मीर के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है. अगर आपको जम्मू-कश्मीर के युवाओं का भविष्य बर्बाद करने में खुशी मिलती है, तो जश्न मनाइए और पटाखे फोड़िए.' वहीं उनकी पार्टी

नेशनल कांफ्रेंस के प्रदेश प्रवक्ता इमरान नबी डार ने एक बयान में कहा है कि यह कदम 'शिक्षा के प्रति भाजपा के लापरवाह और असंवेदनशील रवैये को उजागर करता है.' साथ ही आरोप लगाया कि पार्टी युवाओं के करिअर के साथ ख़तरनाक राजनीति कर रही है।

उन्होंने कहा, 'स्वतंत्र भारत में शायद यह पहला मामला है, जब कोई सांप्रदायिक रूप से विभाजनकारी पार्टी किसी मेडिकल कॉलेज की मान्यता समाप्त किए जाने का जश्न मना रही है. यह व्यवहारिक रूप से एक भयावह स्थिति है और जम्मू के लोगों के लिए एक दुखद क्षण है.' डार ने दावा किया कि यह फैसला न तो आकस्मिक है और न ही तकनीकी, बल्कि यह आपराधिक लापरवाही और गहरे दोषपूर्ण, सांप्रदायिक प्रशासनिक सोच का नतीजा है. उन्होंने कहा, 'केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश दोनों जगह पूर्ण नियंत्रण होने के बावजूद भाजपा अनिवार्य मेडिकल काउंसिल मानकों का बुनियादी पालन तक सुनिश्चित नहीं कर पाई. अचानक सामने आई इन खामियों से गंभीर सवाल उठते हैं और यह कदम भाजपा के विभाजनकारी एजेंडे को छिपाने की कोशिश जैसा दिखता है.'

वहीं, जम्मू-कश्मीर कांग्रेस के प्रवक्ता रवींद्र शर्मा ने कहा कि उन्होंने कहा, 'भाजपा को यह बताना चाहिए कि पवित्र माता वैष्णो देवी जी के नाम पर बने एक प्रमुख मेडिकल संस्थान को बंद कर जम्मू ने आखिर क्या हासिल किया? स्वास्थ्य मंत्रालय, जिसकी जिम्मेदारी जेपी नड्डा के पास है, की विफलता छिपाने के लिए नियमों में बदलाव करने के बजाय जम्मू क्षेत्र को नुकसान झेलना पड़ा.' इससे पहले, आयोग की एक टीम ने 3 जनवरी को रियासी ज़िले के काक्रियाल क्षेत्र में स्थित संस्थान का 'आकस्मिक निरीक्षण' किया था. एसएमवीडी संघर्ष समिति के संयोजक सुखवीर सिंह मंकोटिया ने 4 जनवरी को बयान जारी कर कहा था कि यह निरीक्षण 'समिति के अनुरोध' पर किया गया था।

इससे पहले हिंदुत्व समूहों के समर्थन वाली इस समिति ने मेरिट लिस्ट में केवल दो हिंदू छात्र के नाम आने को 'हिंदुओं के साथ भेदभाव' करार देते हुए जम्मू में बड़े आंदोलन की चेतावनी दी थी. समिति का दावा है कि संस्थान में मुस्लिम और गैर-हिंदू छात्रों की मौजूदगी से कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है. एनएमसी ने इन 50 छात्रों को, जिनका इस साल दाखिला हुआ था, केंद्र शासित प्रदेश के अन्य सरकारी मेडिकल कॉलेजों में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए हैं।

बांग्लादेश में BNP नेता अजीजुर रहमान की गोली मारकर हत्या, भड़के लोगों का प्रदर्शन, सड़कों पर सेना तैनात

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

ढाका- बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मंगलवार रात अज्ञात हमलावरों ने स्वेच्छासेबक दल के पूर्व नेता अजीजुर रहमान मुसब्बिर की गोली मारकर हत्या कर दी. पुलिस और पार्टी सूत्रों के मुताबिक, यह घटना चुनाव से पहले बढ़ती राजनीतिक हिंसा की ताजा कड़ी है. देश में 12 फरवरी को मतदान प्रस्तावित है और उससे पहले आदर्श आचार संहिता लागू है. मुसब्बिर, जो ढाका मेट्रोपॉलिटन नॉर्थ स्वेच्छासेबक दल (बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की स्वयंसेवी इकाई) के महासचिव रह चुके थे, पर करवान बाजार इलाके में रात करीब 8:30 बजे हमला किया गया।

बेहद करीब से मारी गई गोली

पुलिस के अनुसार, सुपर स्टार होटल के पास, बशुंधरा सिटी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नजदीक हमलावरों ने बेहद करीब से गोलियां चलाईं. ये इलाका भीड़भाड़ वाला व्यावसायिक क्षेत्र है. मौके पर ही मुसब्बिर की हालत गंभीर हो गई. गोलीबारी में एक अन्य व्यक्ति भी घायल हुआ, जिसे इलाज के लिए

अस्पताल ले जाया गया. अधिकारियों के मुताबिक, घायल की हालत स्थिर है. ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस के तेजगांव डिविजन के अतिरिक्त उपायुक्त फजलुल करीम ने स्थानीय मीडिया को बताया कि करवान बाजार में स्टार कबाब के पास एक गली में दो लोगों को गोली लगी थी. मुसब्बिर को पहले निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां बाद में उनकी मौत हो गई. उन्हें पेट में गोली लगी थी।

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, घायलों को पहले बीआरबी अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद एक को आगे के इलाज के लिए ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया. जांचकर्ताओं ने बताया कि हमलावरों ने कई राउंड फायरिंग की और फिर फरार हो गए. बुधवार सुबह तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी।

BNP नेता की मौत के बाद क्या है हाल?

घटना के बाद करवान बाजार इलाके में तनाव फैल गया. देर रात कुछ लोगों ने सार्क फाउंटेन चौराहे पर सड़क जाम कर दी, जिससे यातायात ठप हो गया. रात करीब 10:30 बजे सेना के जवान मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को हटाकर रास्ता खुलवाया. हालांकि कुछ देर बाद प्रदर्शनकारी फिर लौट आए, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी और वाहनों को सावधानीपूर्वक गुजरने दिया. पुलिस और सेना की टुकड़ियां कई घंटों तक क्षेत्र में तैनात रहीं ताकि किसी भी नई अशांति को रोका जा सके. अधिकारियों ने कहा कि हमलावरों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए तलाशी अभियान जारी है. गौरतलब है कि बांग्लादेश में इसी साल चुनाव होने वाले हैं. हाल के दिनों में बांग्लादेश में राजनीतिक हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं. कुछ दिन पहले एक जूबो दल नेता को भी गोली मारी गई थी, जबकि 12 दिसंबर को इंकलाब मंच के नेता उस्मान हादी की भी हत्या हो चुकी है. चुनाव से पहले बढ़ती हिंसा ने सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

संक्षिप्त ख़बरें

यह कैसा युद्धविराम ! घर में खेलती बच्ची पर चली गोली, गाजा में सीज़फायर के बाद भी 400 से ज्यादा मौतें

गाजा में घोषित युद्धविराम के लगभग तीन महीने बाद भी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। उत्तरी गाजा के जबालिया इलाके में इज़राइली गोलीबारी से 11 वर्षीय बच्ची हम्सा हुसौ की मौत हो गई। परिजनों के अनुसार, परिवार युद्धविराम के बाद घोषित सुरक्षित क्षेत्र में लौट आया था। बताया गया कि गुरुवार को इज़राइली सैनिकों की कार्रवाई के दौरान गोले और छर्रे बच्ची के घर पर गिरे। गंभीर रूप से घायल हम्सा को शिफा अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्ची के चाचा खामिस हुसौ ने बताया कि हम्सा का सपना डॉक्टर बनने का था। उन्होंने दर्द भरे शब्दों में सवाल उठाया, 'अगर युद्धविराम है तो रोज़ धमाके और गोलियां क्यों चल रही हैं? यह शांति सिर्फ मीडिया में है या ज़मीन पर भी?' परिवार का कहना है कि फल्लूजा मोहल्ले में रोज़ाना गोलीबारी हो रही है, जबकि यह इलाका युद्धविराम रेखा के भीतर आता है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, युद्धविराम लागू होने के बाद से अब तक कम से कम 424 फ़िलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। कुल मिलाकर, इज़राइल-हमास युद्ध में मरने वालों की संख्या 71,000 से अधिक हो गई है, जबकि 1.7 लाख से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इज़राइली सेना ने इस घटना पर तत्काल प्रतिक्रिया नहीं दी है। पहले इज़राइल यह कह चुका है कि युद्धविराम के बाद की सैन्य कार्रवाइयां समझौते के उल्लंघन के जवाब में की गई हैं। हालांकि, लगातार हो रही नागरिक मौतों ने युद्धविराम की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

क्या भाजपा को सताया SIR का डर? सपा मुखिया अखिलेश यादव का दावा- हो रही हैं गुपचुप बैठक

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ- उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत जारी की गई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट ने प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है. चुनाव आयोग की इस प्रारूप मतदाता सूची को लेकर दावा किया जा रहा है कि करीब 2 करोड़ 89 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए हैं. इस मुद्दे पर अब सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी समाजवादी पार्टी आमने-सामने आ गई हैं. इसी बीच, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक लंबा बयान जारी कर भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने इसे वोट काटने की साजिश बताते हुए खासतौर पर पीडीए समाज को सतर्क रहने की अपील की है. उन्होंने लिखा, हर मतदाता और हर 'पीडीए प्रहरी' की जिम्मेदारी है कि पीडीए समाज के वोटों को काटने की किसी भी साजिश को कामयाब न होने दिया जाए. उन्होंने दावा किया कि प्रयासों के बावजूद अभी भी करोड़ों वोट काटे गए हैं. अब जरूरत है कि हर बूथ पर गहन जांच-पड़ताल की जाए और एक भी वोट न कटने पाए, एक भी वोट न घटने पाए के संकल्प के साथ हर वोट बचाया जाए. अपने संदेश में सपा मुखिया ने कहा कि वोटर लिस्ट में नाम होना नागरिक होने की पहचान है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया तो भविष्य में सरकार इसे आधार बनाकर राशन कार्ड, सरकारी योजनाओं, जाति प्रमाणपत्र, आरक्षण, बैंक खाते, पैन कार्ड, आयुष्मान

कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जमीन-जायदाद और घर-मकान तक से नाम हटाने जैसे काले कानून ला सकती है. उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में लोगों को अपने ही देश में बाहरी साबित किया जा सकता है।

अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि जो सरकार निर्विरोध चुनाव कराने का खेल खेल सकती है, वह चुनाव में वोट काटने के लिए कुछ भी कर सकती है. उन्होंने कहा कि भाजपा की मंशा चुनाव जीतकर सरकार बनाना, भ्रष्टाचार करना और जल-जंगल-जमीन पर कब्जा करना है. उन्होंने पीडीए समाज से अपील की कि वह सजग और चौकन्ना रहे, अपना वोट जरूर बनवाए और अपनी नागरिकता, संविधान, आरक्षण और अधिकारों की रक्षा करे. अखिलेश यादव ने कहा कि वोट बचाने का मतलब सिर्फ चुनाव नहीं, बल्कि अपना भविष्य और अधिकार बचाना है. अखिलेश यादव ने पीडीए समाज से सीधी अपील करते हुए लिखा अपना वोट बनाएं, अपना भविष्य बचाएं।

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, वोट बढ़ाने का बीजेपी के लोग दवाब बनाएंगे क्योंकि उनका वोट कट गया है. उन्होंने फर्जी वोट बनाए थे. इसका मतलब फर्जी वोट डाले गए हैं और सबसे ज्यादा वोट बीजेपी के बूथों पर निकले हैं. जिस SIR से ये पूरे देश को परेशान कर रहे थे मैं उत्तर प्रदेश की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं आज SIR से बीजेपी परेशान है और इसलिए गुपचुप बैठक कर रहे हैं...इन लोगों ने 1 करोड़ वोट बढ़वाया है...अब तो सवाल उन पर खड़े हो गए हैं...जो नकली वोट बना रहे हैं उनके खिलाफ FIR हो. वहीं भाजपा ने इन आरोपों पर पलटवार किया है भाजपा प्रवक्ता अशोक पांडेय ने कहा कि अखिलेश जी को यह जानकारी होनी चाहिए कि चुनाव आयोग भाजपा का संगठन नहीं है. जितना हमारा है, उतना ही उनका भी है. हमारे बीएलओ हर बूथ पर हैं. अगर इतना ही है, तो समय बढ़ गया है ,वे चाहें तो अपने बीएलए हर बूथ पर बैठा सकते हैं।

इसपर सपा प्रवक्ता अमीक जमीईन ने कहा की चुनाव आयोग ने एसआईआर के ज़रिये एनआरसी कराने का काम किया है. ऐसे में जिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, अगर उनका वोट कट गया तो उन्हें दोबारा कैसे शामिल किया जाएगा, यह एक बड़ी समस्या है. कल आप उन्हें सरकारी योजनाओं में मदद नहीं देंगे, उनकी नागरिकता छीनी जाएगी. साल 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, इसलिए वोट काटने की साज़िश की जा रही है. हमारा हर नागरिक से निवेदन है कि अपने वोट का ध्यान रखें. वोट जोड़ने का काम पीडीए प्रहरी कर रहे हैं, उनकी मदद लें. साथ ही सरकार को इस पर और सोचने के लिए समय लेना चाहिए।

अम्बेडकरनगर में ग्रामर्षि महोत्सव का भव्य आयोजन, 200 से अधिक युवाओं को मिले रोजगार पत्र

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

अम्बेडकरनगर- जनपद में ग्रामर्षि महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सेवा का अनूठा संगम देखने को मिला। सया डिग्री कॉलेज परिसर में आयोजित इस महोत्सव में अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या के कुलपति भी विशेष रूप से शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 200 से अधिक बेरोजगार युवकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। एक ही मंच से इतने युवाओं को रोजगार मिलने से क्षेत्र में खुशी और उत्साह का माहौल देखा गया। रोजगार मेले में कुल 208 युवाओं को विभिन्न संस्थानों द्वारा नियुक्ति पत्र दिए गए। आयोजकों के अनुसार, यह पहला अवसर है जब किसी शिक्षण संस्थान में एक साथ इतने अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हों। इसे एक ऐतिहासिक क्षण बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे ग्रामीण युवाओं के लिए नई दिशा देने वाला कदम बताया। महोत्सव के दौरान सामाजिक सरोकार को भी प्राथमिकता दी गई। एक हजार से अधिक असहाय और जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए गए, जिससे ठंड के मौसम में उन्हें राहत मिली। इस मानवीय पहल की चारों ओर प्रशंसा हो रही है। गौरतलब है कि ग्रामर्षि महोत्सव का आयोजन पिछले 18 वर्षों से लगातार अम्बेडकरनगर जनपद के सया डिग्री कॉलेज में किया जा रहा है। यह आयोजन ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की अलख जगाने वाले पंडित रामकुमार पाण्डेय की स्मृति में उनके पुत्र, पूर्व सांसद एवं वर्तमान विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) हरिओम पाण्डेय द्वारा हर वर्ष कराया जाता है। महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ-साथ मेधावी छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया जाता है। इस अवसर पर एमएलसी हरिओम पाण्डेय ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में उनके पिता द्वारा लगाया गया वटवृक्ष आज फल-फूल रहा है। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि ग्रामर्षि की आत्मा आज यह देखकर संतुष्ट होगी कि उनकी सोच और संघर्ष से शुरू हुआ यह अभियान अब ख्याति प्राप्त कर रहा है। उन्होंने बताया कि रोजगार मेला युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है और आने वाले वर्षों में इसे और व्यापक रूप दिया जाएगा।

कोयला, कैश और I-PAC: 2700 करोड़ के सिंडिकेट में ED की स्ट्राइक, लेकिन क्यों उड़ी ममता दीदी की नींद

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

पश्चिम बंगाल की सियासत में गुरुवार को नया खेला हो गया. ईडी ने जब तृणमूल कांग्रेस के लिए चुनावी बिसात बिछाने वाली कंपनी I-PAC (इंडियन पोलिटिकल एक्शन कमेटी) के दफ्तरों पर दस्तक दी, तो कोलकाता से लेकर दिल्ली तक खलबली मच गई. ममता बनर्जी की नींद उड़ गई है. वह गुस्से से लाल हैं और केंद्र सरकार पर हमले कर रही हैं. उधर, ईडी सूत्रों का कहना है कि एक कोयला घोटाले से I-PAC के कनेक्शन जुड़ रहे हैं, इसलिए छापेमारी की गई. इसका किसी राजनीतिक दल से कोई रिश्ता नहीं है. तो आखिर ऐसा क्या है कि एक कंपनी पर पड़े छापे ने दीदी की नींद उड़ा दी है? कोयला, कैश और I-PAC के पूरे सिंडिकेट को समझिए।

ईडी सूत्रों के मुताबिक, कहानी शुरू होती है आसनसोल और रानीगंज की उन खदानों से, जो केंद्र सरकार की कंपनी ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के अधिकार क्षेत्र में आती हैं।

खेल क्या था?

सरकारी खदानों से रात के अंधेरे में हजारों टन कोयला खोदा गया और चोरी-छिपे बेच दिया गया. यह कोई छोटी-मोटी चोरी नहीं थी.

श्रष्ठ की जांच बताती है कि करीब 2,742.32 करोड़ का कोयला सरकारी तंत्र की नाक के नीचे से गायब कर दिया गया।

सिंडिकेट का 'गॉडफादर'

इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड अनुप माजी उर्फ लाला था. लाला का नेटवर्क इतना तगड़ा था कि पुलिस, CISF, रेलवे और श्रष्टर के कुछ भ्रष्ट अधिकारी उसकी जेब में थे. 2000 से 2015 के बीच उस पर 16 एफआईआर हुईं, लेकिन उसका रसूख उसे हर बार बचाता रहा।

फिर I-PAC की एंट्री

अब तक यह मामला सिर्फ कोयला चोरी का था, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब ईडी ने मनी ट्रेल यानी पैसों के ट्रांजेक्शन का रास्ता खंगालना शुरू किया . जांच एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक, कोयला घोटाले से कमाए गए करोड़ों रुपये हवाला नेटवर्क के जरिए इधर-उधर किए गए. जांच में एक सिरा I-PAC और उसके निदेशकों की तरफ मुड़ता दिखा. आरोप है कि सिंडिकेट का पैसा कुछ शेल कंपनियों और ट्रांजेक्शन के जरिए I PAC तक पहुंचा. इसी सबूत की तलाश में ईडी ने दिल्ली और बंगाल में 10 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की।

ममता बनर्जी पर ईडी का सनसनीखेज आरोप: 'रेड में घुसकर ले गई सबूत'

मामले ने तब बेहद गंभीर मोड़ ले लिया जब ईडी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जांच में सीधे तौर पर बाधा डालने और सबूत मिटाने का बड़ा आरोप लगाया. एजेंसी का दावा है कि छापेमारी शांतिपूर्ण चल रही थी, लेकिन तभी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भारी पुलिस बल के साथ प्रतीक जैन के आवास और I-PAC के कार्यालय पहुंचीं. आरोप है कि उन्होंने वहां से जबरन अहम दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अपने कब्जे में ले लिए. ईडी ने इसे मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) की कार्रवाई में गंभीर अवरोध और कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन बताया है. हालांकि, एजेंसी ने यह भी साफ किया कि यह रेड राजनीति से प्रेरित नहीं थी और न ही किसी पार्टी दफ्तर पर छापा मारा गया था, लेकिन मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप ने जांच को प्रभावित किया है।

न विरोध न टकराव मगर खींच दी बड़ी लकीर, नुसरत परवीन का एक फैसला और तीन संदेश, समाज के लिए बनी मिसाल

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

पटना- बीते 15 दिसंबर को बिहार के मुख्यमंत्री सचिवालय में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान सीएम नीतीश कुमार हिजाब हटाने को लेकर उठा विवाद अचानक डॉ. नुसरत परवीन को राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना गया. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, बयानबाज़ी हुई, आरोप-प्रत्यारोप चले. कुछ ने इसे महिला सम्मान से जोड़ा तो कुछ ने इसे राजनीति का हथियार बना लिया. इन सबके बीच जो विवाद की केंद्र बिंदु रहीं वर बिल्कुल खामोश रहीं. नुसरत परवीन ने इस मुद्दे पर न कोई उग्र बयान दिया, न कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया दी और न ही किसी पर कोई आरोप ही लगाए. वह विवाद के केंद्र में तो हर वक्त रहीं, लेकिन उन्होंने खुद को सियासत के मचाए जाने वाले शोर से पूरी तरह अलग रखा. संभवतः अंत में यही उनके फैसले की सबसे बड़ी ताकत भी रही।

महिला सम्मान और नुसरत की समझदारी

जानकारों की नजर में इस हिजाब प्रकरण से नुसरत परवीन आहत तो अवश्य हुईं लेकिन उनका पूरा रुख महिला सम्मान के इर्द-गिर्द रहा. उन्होंने न तो किसी भी प्रकार की कट्टरता को हवा दी और न ही सांप्रदायिक राजनीति का हिस्सा बनीं. इस बीच उन्होंने यह संदेश दिया कि एक महिला अपने आत्मसम्मान, अपनी पहचान और अपने करियर-तीनों को साथ लेकर चल सकती हैं. आज जब बहस

अक्सर दो ध्रुवों में बंट जा या करती हैं, ऐसे में नुसरत परवीन का यह संतुलन भरा आचरण समाज और नई पीढ़ी के लिए एक सीख है. खास संदेश सत्ता के लिए भी है कि ऐसे मामलों में संवेदनशीलता और संतुलन कितनी जरूरी है।

करियर को प्राथमिकता, समाज को संदेश

23 दिन तक नौकरी ज्वाइन न करना कई सवाल खड़े करता रहा. कुछ रिपोर्टों में उनकी नाराजगी की बातें भी सामने आईं. लेकिन अंत में जब उन्होंने सेवा में योगदान दिया तो उन तमाम अटकलों पर विराम लग गया. सदर पीएचसी में तैनाती के साथ उन्होंने यह साफ कर दिया कि उनका रास्ता सेवा, चिकित्सा और प्रोफेशनल जिम्मेदारी से होकर जाता है. यह फैसला उन युवाओं के लिए भी संदेश है जो किसी एक घटना के बाद भावनाओं में बहकर अपने भविष्य को दांव पर लगा देते हैं।

कट्टरता और राजनीति-दोनों को आईना

नुसरत परवीन का कदम उन लोगों को भी आईना दिखाता है जो हर महिला को किसी प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं. यह फैसला उन ताकतों के लिए भी जवाब है जो धर्म के नाम पर समाज को बांटने में लगे रहते हैं. नुसरत ने न किसी को चुनौती दी, न किसी से टकराव किया. उन्होंने बस अपना स्वयं का रास्ता चुना और वही सबसे मजबूत जवाब बन गया. यह कदम उन लोगों के लिए आईना है, जो हर मुद्दे को धर्म और कट्टरता के चश्मे से देखने के आदी हो चुके हैं।

सियासी शोर में समाज के लिए बड़ी बात

झराजकीय तिब्बी कॉलेज से एमडी पीजी कर रही एक युवा डॉक्टर का यह फैसला बताता है कि बदलाव नारे से नहीं आचरण से आता है. डॉ. नुसरत परवीन ने यह साबित किया कि असली साहस विवाद में उलझना नहीं, बल्कि उससे ऊपर उठकर अपने कर्तव्य को निभाना है. नौकरी ज्वाइन कर उन्होंने अपने करियर को भी तवज्जो दी और समाज को भी एक सकारात्मक संदेश दिया कि सम्मान, पहचान और प्रोफेशनलिज़्म साथ-साथ चल सकते हैं।

दंगाइयों को कानून का कवच देने से शीर्ष अदालत का इंकार

दिल्ली के दंगाइयों को शीर्ष अदालत ने राहत देने से सीधा इंकार कर दिया यह अदालत की अराजकता से निबटने की जीरो टॉलरेंस की नीति का हवाला देता है। उच्चतम न्यायालय ने 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में आरोपियों उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से साफ इंकार करते हुए कहा है कि उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनता है। अदालत ने साथ ही उमर खालिद और शरजील इमाम पर इस मामले में एक साल तक जमानत याचिका दाखिल करने पर भी रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने हालांकि इस मामले में अन्य आरोपियों गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को 12 शर्तों के साथ जमानत दे दी है। पीठ ने कहा, 'अदालत इस बात से संतुष्ट है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत सामग्री से याचिकाकर्ताओं उमर खालिद और शरजील इमाम के खिलाफ प्रथम दृष्टया आरोप सिद्ध होते हैं। इन याचिकाकर्ताओं के संबंध में वैधानिक कसौटी लागू होती है। कार्यवाही के इस चरण में उन्हें जमानत पर रिहा करना उचित नहीं है।' अदालत ने कहा कि जिन लोगों को जमानत मिली है, उनकी भूमिका सीमित और परिस्थितिजन्य मानी गई है, जबकि उमर खालिद और शरजील इमाम पर दंगों की साजिश रचने, भीड़ को भड़?काने और सुनियोजित तरीके से हिंसा को दिशा देने के गंभीर आरोप हैं। अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर हिंसा को जायज नहीं ठहराया जा सकता। देखा जाये तो उच्चतम न्यायालय का यह फैसला केवल दो व्यक्तियों की जमानत याचिका का निपटारा नहीं है, बल्कि यह देश की आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और राष्ट्रीय संकल्प का स्पष्ट संदेश है। आपको पता रहे उमर खालिद और शरजील इमाम जैसे लोग कोई साधारण आरोपी नहीं हैं। ये वे चेहरे हैं जिन्होंने विचारधारा की आड़ में सड़कों पर आग लगाने की मानसिकता को खाद पानी दिया। यह वार बार साबित हो चुका है कि दिल्ली दंगे अचानक नहीं भड़?के थे। उनके पीछे शब्दों के बारूद, भाषणों की चिंगारी और योजनाबद्ध उकसावे की लंबी तैयारी थी।

ऐसे मामलों में यदि अदालत नरमी दिखाती, तो यह न केवल न्याय के साथ अन्याय होता बल्कि समाज के लिए एक खतरनाक संकेत भी जाता। अदालत ने सही कहा कि इन दोनों की स्थिति अन्य आरोपियों से अलग है। यह अंतर केवल कानूनी नहीं, बल्कि नैतिक और सामाजिक भी है। दंगा केवल पत्थर फेंकने से नहीं होता, दंगा उस सोच से पैदा होता है जो समाज को बांटने का काम करती है। जब किसी मंच से यह कहा जाए कि सड़?कों पर उतर कर व्यवस्था को जाम कर दो, तब वही शब्द बाद में आग बन जाते हैं। जमानत खारिज करने का फैसला उन सभी लोगों के लिए चेतावनी है जो खुद को एक्टिविस्ट या बुद्धिजीवी बताकर कानून को ठेंगा दिखाना चाहते हैं। यह फैसला बताता है कि भारत में अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब अराजकता फैलाने की छूट नहीं है। मुकदमे में देरी को लेकर अदालत की टिप्पणी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। वर्षों से एक तर्क गढ़ लिया गया था कि अगर मुकदमा लंबा चल रहा है, तो आरोपी को स्वतः राहत मिलनी चाहिए। यह सोच न्याय व्यवस्था को कमजोर करती है। अगर गंभीर साजिशों में केवल समय के आधार पर जमानत मिलने लगे, तो हर देश विरोधी ताकत समय को हथियार बना लेगी। इस फैसले का सबसे बड़ा असर उपद्रवी और दंगाई मानसिकता वाले लोगों पर पड़ेगा। अब यह भ्रम टूटेगा कि लंबी कानूनी प्रक्रिया अंततः उन्हें बचा लेगी। देखा जाये तो अदालत का सख्त रुख भारत की आतंकवाद के खिलाफ चल रही लड़ाई को मजबूत करता है। आपको बता दें यह फैसला उन आम नागरिकों के लिए भी भरोसे का आधार है जिन्होंने दंगों में अपने घर, दुकानें और परिजन खोए। उनके लिए न्याय केवल सजा नहीं, बल्कि यह विश्वास है कि सिस्टम उनके साथ खड़ा है। कुछ लोग इसे कठोरता कहेंगे, लेकिन सच यह है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए कठोर फैसले जरूरी होते हैं। उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत खारिज होना इस बात का प्रमाण है कि भारत की न्यायपालिका आज भी राष्ट्र की सुरक्षा, सामाजिक सौहार्द और संविधान की मूल भावना को समझती है। यह फैसला आने वाले समय में न केवल कानूनी मिसाल बनेगा, बल्कि उन सभी ताकतों के लिए एक स्पष्ट चेतावनी भी होगा जो भारत को भीतर से तोड़ने का सपना देखती हैं। यह निर्णय बताता है कि भारत कमजोर नहीं है, भारत चुप नहीं है और भारत अब दंगों की राजनीति को बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। हालिया कानूनी घटनाक्रमों और न्यायिक टिप्पणियों के अनुसार, खुद को एक्टिविस्ट या बुद्धिजीवी बताकर कानून से ऊपर समझने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्ती बढ़ी है। अदालतों ने स्पष्ट किया है कि एक्टिविस्ट या बुद्धिजीवी होने का लेबल किसी व्यक्ति को आपराधिक जांच या कानूनी प्रक्रिया से सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। कानून की नजर में सभी नागरिक समान हैं। पिछले कुछ वर्षों में भीमा कोरेगांव और दिल्ली दंगों जैसे मामलों में कई चर्चित चेहरों की गिरफ्तारियों और अदालतों द्वारा उनकी जमानत याचिकाओं को खारिज किए जाने को इस दिशा में एक बड़ा झटका माना गया है। जांच एजेंसियों ने इन पर अर्बन नक्सल या देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगाए हैं। यूएपीए जैसे कड़े कानूनों के तहत की गई कार्रवाई और अदालतों द्वारा साक्ष्यों के आधार पर दी गई कड़ी टिप्पणियों ने यह संदेश दिया है कि वैचारिक स्वतंत्रता की आड़ में हिंसा या अस्थिरता को बढ़ावा देना स्वीकार्य नहीं होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न मामलों में कहा है कि विरोध का अधिकार मौलिक है, लेकिन यह कानून के शासन के उल्लंघन का अधिकार किसी को नहीं देता है। जाहिर है कि कानून का शासन बनाए रखने के लिए अदालत का भी सख्त रुख होना अत्यंत महत्वपूर्ण है इसके बिना सामूहिक गुंडई अराजकता फैलाने और भीड़ तंत्र कायम करने के षडयंत्रों पर नकेल डालना संभव नहीं होगा।

मनोज कुमार अग्रवाल

नशे की संगती, जीवन की बड़ी विपत्ति वर्तमान यथार्थ और समाधान का भविष्य

नशा मानव जीवन की उन कमजोरियों में से एक है, जिसने युगों-युगों से व्यक्ति, परिवार और समाज को भीतर से क्षीण किया है। यह केवल आधुनिक समय की समस्या नहीं है, बल्कि इसके बीज पौराणिक काल तक फैले हुए दिखाई देते हैं। किंतु यह भी उतना ही सत्य है कि भारतीय पौराणिक परंपरा ने नशे को कभी जीवन-मूल्य नहीं माना, बल्कि उसे पतन का कारण बताया और आत्मसंयम को श्रेष्ठ गुण के रूप में प्रतिष्ठित किया। पौराणिक काल में नशे का उल्लेख प्रतीकात्मक और सीमित रूप में मिलता है। देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन से प्राप्त 'सुरा' और 'सोम' का प्रसंग प्रसिद्ध है। किंतु यह समझना आवश्यक है कि सोम कोई सामान्य नशीला पेय नहीं था, बल्कि वह यज्ञीय और औषधीय प्रयोजनों से जुड़ा दिव्य तत्व था, जिसका प्रयोग केवल विशेष अवसरों पर और संयमित रूप में होता था। इसके विपरीत, जब सुरा का प्रयोग असंयम और भोग के लिए हुआ, तो उसका परिणाम विनाशकारी सिद्ध हुआ। पुराणों में असुरों का पतन अक्सर उनकी भोगवादी प्रवृत्ति और मद्यपान से जोड़ा गया है, जो यह संकेत देता है कि नशा विवेक और मर्यादा के क्षय का कारण बनता है। महाभारत में यदुवंश का विनाश नशे के दुष्परिणामों का सबसे सशक्त उदाहरण है। द्वारका में यादवों के बीच मद्यपान से उत्पन्न उन्माद ने उन्हें आपस में ही विनाश की ओर धकेल दिया। यह प्रसंग स्पष्ट संदेश देता है कि नशा केवल व्यक्ति को नहीं, बल्कि पूरे वंश और समाज को नष्ट कर सकता है। रामायण में भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम का जीवन पूर्ण संयम और आत्मनियंत्रण का आदर्श है। वहाँ नशा कहीं भी आदर्श जीवन का अंग नहीं बनता, बल्कि त्याग, तप और संयम को ही श्रेष्ठ माना गया है। बौद्ध और जैन परंपराओं ने तो नशे के विरुद्ध और भी स्पष्ट रुख अपनाया। भगवान बुद्ध के पंचशील में नशा न करने की प्रतिज्ञा आत्मिक जागरण की अनिवार्य शर्त है। महावीर स्वामी ने इंद्रिय संयम को मोक्ष का द्वार बताया। इन सभी परंपराओं का मूल संदेश यही है कि नशा मनुष्य को उसके लक्ष्य से भटका देता है और आत्मविकास के मार्ग में बाधा बनता है। आज के समय में नशे की समस्या कहीं अधिक विकराल रूप ले चुकी है। शराब, तंबाकू, गुटखा, अफीम और सिंथेटिक ड्रग्स ने समाज के हर वर्ग को प्रभावित किया है, विशेषकर युवा पीढ़ी को। नशा आज केवल व्यक्तिगत कमजोरी नहीं, बल्कि संगठित अपराध, बेरोजगारी, पारिवारिक विघटन और मानसिक रोगों का कारण बन चुका है। इसका प्रभाव राष्ट्र की उत्पादकता और सामाजिक ताने-बाने पर भी पड़ता है। नशे के विरुद्ध प्रभावी संघर्ष के लिए बहुआयामी प्रयास आवश्यक हैं। सबसे पहले, सामाजिक चेतना का निर्माण करना होगा। पौराणिक कथाओं और ऐतिहासिक उदाहरणों के माध्यम से यह समझाया जा सकता है कि नशा सदैव पतन का कारण रहा है। शिक्षा संस्थानों में नैतिक शिक्षा, योग, ध्यान और जीवन-कौशल को अनिवार्य किया जाना चाहिए, ताकि युवा तनाव से निपटने के लिए नशे का सहारा न लें। दूसरे, परिवार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। संवादहीनता और भावनात्मक रिक्तता नशे की ओर पहला कदम होती है। यदि परिवार बच्चों को समय, स्नेह और सही मार्गदर्शन दे, तो नशे की संभावना स्वतः कम हो जाती है। तीसरे, शासन और समाज को मिलकर नशे के व्यापार पर कठोर नियंत्रण करना होगा। केवल कानून नहीं, बल्कि पुनर्वास

और परामर्श केंद्रों का विस्तार भी आवश्यक है, ताकि नशे में फँसे व्यक्ति को अपराधी नहीं, रोगी समझकर उपचार दिया जा सके। अंततः, नशे के विरुद्ध संघर्ष एक निरंतर अभियान है, न कि एक बार का कार्यक्रम। पौराणिक काल से लेकर आज तक का अनुभव यही सिखाता है कि जहाँ संयम, विवेक और मूल्य रहे, वहाँ समाज फला-फूला; और जहाँ नशा जीवन-शैली बना, वहाँ विनाश अवश्यंभावी हुआ। आज आवश्यकता है कि हम अपने सांस्कृतिक मूल्यों की ओर लौटते हुए नशा-मुक्त, स्वस्थ और सशक्त समाज के निर्माण का संकल्प लेना होगा।

संजीव ठाकुर

विश्व राजनीति में अमेरिका की जिद और ट्रम्प की सोच शक्तिप्रदर्शन से उपजी वैश्विक बेचैनी का यथार्थ

अमेरिका की विदेश नीति लंबे समय से शक्ति के प्रदर्शन और दबाव की रणनीति पर आधारित रही है। डोनाल्ड ट्रम्प के राष्ट्रपति बनने के बाद यह प्रवृत्ति और अधिक आक्रामक रूप में सामने आई। ट्रम्प जिस विचार को मन में रखते हैं उसे लागू करने के लिए वे किसी भी हद तक जाने को तैयार दिखाई देते हैं। वेनेजुएला पर हमला इसी सोच का परिणाम माना जा रहा है। इस हमले ने न केवल लैटिन अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। भारत ने भी वेनेजुएला की स्थिति पर चिंता व्यक्त की है क्योंकि दोनों देशों के संबंध पारंपरिक रूप से मैत्रीपूर्ण रहे हैं। ट्रम्प की विचारधारा मूल रूप से अमेरिका फर्स्ट की अवधारणा पर टिकी है। इस अवधारणा में सहयोग से अधिक दबाव और साझेदारी से अधिक आदेश की भावना झलकती है। ट्रम्प मानते हैं कि वैश्विक व्यवस्था में अमेरिका को सर्वोच्च रहना चाहिए और यदि इसके लिए सैन्य शक्ति आर्थिक प्रतिबंध या राजनीतिक धमकी का सहारा लेना पड़े तो वह भी उचित है। वेनेजुएला पर हमला इसी मानसिकता का प्रतीक है। वहां के राष्ट्रपति मदुरो के खिलाफ वर्षों से चल रहे अमेरिकी विरोध ने अंततः सैन्य कार्रवाई का रूप ले लिया। इस हमले में निर्दोष नागरिकों को भारी नुकसान हुआ है। मदुरो की पत्नी के घायल होने की खबर ने इस संघर्ष की मानवीय कीमत को उजागर किया है। आंख के पास लगी चोट केवल एक व्यक्ति की पीड़ा नहीं बल्कि उस समाज की पीड़ा का प्रतीक है जो महाशक्तियों की लड़ाई में पिस जाता है। युद्ध का सबसे बड़ा शिकार आम नागरिक ही बनते हैं जिनका सत्ता संघर्ष से कोई लेना देना नहीं होता। यूरोप के कई देशों ने ट्रम्प की नीतियों का खुलकर विरोध किया है। वेनेजुएला के मामले में यूरोपीय देशों ने अमेरिका के एकतरफा रवैये पर सवाल उठाए हैं। ड्रेनमार्क के प्रधानमंत्री का बयान कि ग्रीनलैंड पर हमला हुआ तो नाटो समाप्त हो जाएगा यह दर्शाता है कि अमेरिकी तानाशाही से उसके पारंपरिक सहयोगी भी असहज हैं। यह बयान केवल एक चेतावनी नहीं बल्कि वैश्विक गठबंधनों में बढ़ती दरार का संकेत है। भारत और अमेरिका के संबंधों को अक्सर रणनीतिक साझेदारी कहा जाता है लेकिन हाल के वर्षो में इसमें भी तनाव के संकेत मिले हैं। अमेरिका द्वारा भारत से रूस से कच्चा तेल खरीदने पर आपत्ति जताना इसी का उदाहरण है। यह कहना कि अमेरिका को खुश करने के लिए भारत को अपनी ऊर्जा नीति बदलनी होगी सीधे तौर पर संप्रभुता पर सवाल है। भारत ने हमेशा स्वतंत्र विदेश नीति का पालन किया है और किसी भी दबाव में निर्णय लेने से परहेज किया है। भारत सैन्य शक्ति में किसी से कम नहीं है। उसकी रणनीतिक क्षमता और क्षेत्रीय प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यदि अमेरिका की नीति केवल धमकी और दबाव तक सीमित न रहकर आक्रामक होती तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते थे। सौभाग्य से अभी यह टकराव शब्दों और नीतिगत दबाव तक सीमित है लेकिन यह स्थिति भी चिंता पैदा करने वाली है। लैटिन अमेरिका में अमेरिका की छवि लगातार खराब हो रही है। कोलंबिया के राष्ट्रपति पेट्रो का बयान कि किसी को धमकी देना ठीक नहीं है इस असंतोष को दर्शाता है। ट्रम्प द्वारा कोलंबिया को बीमार देश कहना औपनिवेशिक मानसिकता की याद दिलाता है। यह भाषा सम्मानजनक कूटनीति के विपरीत है और इससे देशों के बीच अविश्वास बढ़ता है। यदि अमेरिका ने वेनेजुएला जैसे देशों में हस्तक्षेप जारी रखा तो वहां गुरिल्ला युद्ध भड़कने की आशंका है। इतिहास गवाह है कि बाहरी हस्तक्षेप अक्सर लंबे और रक्तरंजित संघर्ष को जन्म देता है। अफगानिस्तान और इराक इसके उदाहरण हैं जहां सैन्य विजय के दावे तो किए गए लेकिन स्थायी शांति नहीं आ सकी। अमेरिका की नीतियों का असर केवल प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित देशों तक सीमित नहीं रहता। वैश्विक अर्थव्यवस्था ऊर्जा बाजार और अंतरराष्ट्रीय राजनीति सभी इससे प्रभावित होते हैं। वेनेजुएला तेल संपदा से भरपूर देश है और वहां अस्थिरता का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। भारत जैसे विकासशील देशों को ऊर्जा सुरक्षा के लिए संतुलन साधना पड़ता है लेकिन अमेरिकी दबाव इस संतुलन को कठिन बना देता है। ट्रम्प की विचारधारा में कूटनीति से अधिक व्यापारिक सौदे और शक्ति का प्रदर्शन दिखाई देता है। वे रिश्तों को लाभ और हानि के तराजू पर तौलते हैं। जो देश उनकी शर्तें मानते हैं वे मित्र कहलाते हैं और जो विरोध करते हैं वे शत्रु की श्रेणी में आ जाते हैं। यह दृष्टिकोण वैश्विक सहयोग की भावना को कमजोर करता है। निर्दोष देशों और समाजों पर इस राजनीति का गहरा असर पड़ता है। युद्ध और प्रतिबंधों से आम लोगों की जिंदगी कठिन हो जाती है। बच्चों की शिक्षा रुक जाती है स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होती हैं और गरीबी बढ़ती है। इन मानवीय पहलुओं पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता क्योंकि सत्ता की भाषा

में केवल रणनीति और हित गिने जाते हैं। आज दुनिया बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ रही है। चीन रूस भारत और यूरोपीय संघ जैसी शक्तियां अपने अपने क्षेत्र में प्रभाव बढ़ा रही हैं। ऐसे समय में अमेरिका का एकतरफा रवैया उसे अलग थलग कर सकता है। सहयोग और संवाद के बिना वैश्विक चुनौतियों का समाधान संभव नहीं है। जलवायु परिवर्तन आतंकवाद और आर्थिक असमानता जैसे मुद्दे सामूहिक प्रयास मांगते हैं। अमेरिका को यह समझना होगा कि शक्ति का स्थायी आधार नैतिकता और विश्वास होता है न कि केवल सैन्य बल। ट्रम्प की नीतियों ने अल्पकालिक दबाव तो बनाया है लेकिन दीर्घकाल में इससे अमेरिका की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा है। मित्र देश भी अब सोचने लगे हैं कि क्या अमेरिकी नेतृत्व भरोसेमंद है। अंततः यह समय आत्ममंथन का है। अमेरिका यदि सच में वैश्विक नेतृत्व चाहता है तो उसे तानाशाही के स्थान पर साझेदारी का मार्ग चुनना होगा। वेनेजुएला भारत कोलंबिया या यूरोप सभी यह संकेत दे रहे हैं कि दुनिया अब आदेश नहीं संवाद चाहती है। निर्दोष लोगों की पीड़ा को समझे बिना बनाई गई नीतियां इतिहास में कठोर रूप से आंकी जाएंगी।

कांतिलाल मांडोत

संपादकीय

मतदाता सूची का मेगा रीसेटः जनता, वोट और सत्ता की जंग

मृतक, डुप्लीकेट और गायब नामः लोकतंत्र की परीक्षा यूपी में
[मतदाता सूची की सफाईः अधिकार सुरक्षित या लोकतंत्र कमजोर?]

उत्तर प्रदेश में हाल ही में मतदाता सूची में बड़ा संशोधन आया, जिसने राजनीति और प्रशासन दोनों में हलचल मचा दी है। 2.89 करोड़ नाम हटने के बाद लोकतंत्र की नींव पर गंभीर प्रश्न उठ खड़े हुए हैं। क्या यह कदम चुनावों को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने की वास्तविक कोशिश है, या सत्ता की चालाकी और रणनीति का हिस्सा मात्र? देश के सबसे बड़े राज्य में इस बदलाव ने व्यापक बहस को जन्म दिया है। शुद्धता के दावे और अन्याय के आरोपों के बीच जनता उलझन में है। ड्राफ्ट सूची में यह विशाल संशोधन दिखाता है कि मतदाता सूची केवल कागजी दस्तावेज़ नहीं, बल्कि लोकतंत्र की रीढ़ और उसकी विश्वसनीयता का प्रमाण है। चुनाव आयोग ने 6 जनवरी 2026 को ड्राफ्ट सूची जारी की, जिसमें कुल 15.44 करोड़ मतदाताओं में से 2.89 करोड़ नाम हटा दिए गए। अब कुल वैध नाम केवल 12.55 करोड़ बचे हैं। हटाए गए नामों में 46.23 लाख मृतक, 2.17 करोड़ स्थानांतरित और 25.47 लाख डुप्लिकेट नाम शामिल हैं। यह कुल मतदाताओं का 18.7 प्रतिशत है, जो भारत में किसी भी राज्य में सबसे बड़ा संशोधन माना जा रहा है। एसआईआर की समयसीमा और ड्राफ्ट प्रकाशन कई बार बढ़ाया गया, क्योंकि सूची में बड़े पैमाने पर असंगतियां मिलीं। दावा-आपत्ति की अवधि 6 फरवरी तक है, जिससे सभी प्रभावित लोग फॉर्म भरकर नाम जोड़ सकते हैं। इस विशाल हटाव ने सवाल खड़े किए हैं कि क्या यह लोकतंत्र को मजबूत करने का कदम है, या लक्षित राजनीतिक कार्रवाई है। लोकतंत्र की शुद्धता के समर्थक इसे ऐतिहासिक सुधार कहते हैं। उनके अनुसार, मृतक और डुप्लिकेट नाम चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। इससे वोटिंग सिस्टम में फर्जीवाड़ा रोका जा सकता है। एसआईआर प्रक्रिया के अनुसार, 81.3 प्रतिशत मतदाताओं ने गणना फॉर्म जमा किए, जबकि बाकी नहीं कर सके। इस तरह की सफाई अन्य राज्यों में भी हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश में कटौती सर्वाधिक रही। समर्थकों का कहना है कि इससे वोट बैंक की राजनीति कमजोर होगी और असली मतदाताओं की आवाज़ को ताकत मिलेगी। विपक्षी दल इसे राजनीतिक साजिश मान रहे हैं। उनका तर्क है कि गरीब और अल्पसंख्यक समुदाय के वोटों को प्रभावित किया जा रहा है। कई नेता और उनके परिवार के नाम हटाए जाने का दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि केवल निवास बदलने के कारण वैध मतदाताओं को बाहर किया गया। विरोधियों का आरोप है कि यह लोकतंत्र पर हमला है और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। शहरी क्षेत्रों और प्रवासी आबादी में अधिक नाम हटाए गए हैं, जिससे यह आशंका बढ़ रही है कि यह उद्देश्यपूर्ण कार्रवाई हो सकती है। तथ्यों की पड़ताल करें तो आयोग ने हटाव के स्पष्ट कारण बताए हैं–मृत्यु, स्थानांतरण और डुप्लिकेट नाम। लखनऊ और गाजियाबाद जैसे शहरी केंद्रों में सबसे ज्यादा नाम हटाए गए। घर-घर जाकर फॉर्म भरवाए गए और 91 प्रतिशत से अधिक मैपिंगकी गई। शेष को नोटिस भेजे जा रहे हैं। बावजूद इसके, इतनी बड़ी संख्या ने संदेह पैदा कर दिया है। क्या सभी फॉर्म न जमा करने वाले असली मतदाता नहीं हैं? आयोग का कहना है कि दावा-आपत्ति प्रक्रिया में सुधार संभव है और यह निष्पक्षता दिखाती है। विपक्ष का कहना है कि दस्तावेज जुटाने में गरीब और अनपढ़ मतदाताओं को दिक्कत होगी, जिससे लोकतंत्र की वैधता पर सवाल उठते हैं। इस संशोधन का आगामी चुनावों पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें निर्णायक मानी जाती हैं। अगर वैध मतदाता भी हट गए, तो वोट प्रतिशत और चुनाव परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। समर्थक इसे फर्जीवाड़ा रोकने का कदम मानते हैं, जबकि विपक्ष इसे वोट दबाने की रणनीति कह रहा है। एसआईआर की अवधि बढ़ने से सत्यापन बेहतर हुआ, लेकिन गरीब और अल्पसंख्यक समुदाय इससे सबसे अधिक प्रभावित हो सकते हैं। यह सवाल उठता है कि क्या प्रक्रिया पर्याप्त पारदर्शी है या नहीं। समाज पर नजर डालें तो प्रवासी मजदूर, शहरी गरीब और छोटे शहरों के मतदाता सबसे प्रभावित हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्र भी इससे अछूते नहीं रहे। विपक्ष इसे मतदाता दमन मान रहा है। वहीं आयोग का कहना है कि मृतक नाम हटाना अनिवार्य था और यह रूटीन प्रक्रिया है। अन्य राज्यों में भी ऐसा सुधार होना चाहिए। मतदाता सूची की शुद्धता ही चुनाव की नींव है। अगर फर्जी नाम मौजूद रहें, तो लोकतंत्र कमजोर होगा। वहीं वैध नाम हटने से अन्याय होगा। जनता को जागरूक होना आवश्यक है। आगे की राह में आयोग के लिए पूर्ण पारदर्शिता

अनिवार्य हो गई है। दावा-आपत्ति की अवधि में लाखों मतदाता अपने अधिकार को सुरक्षित कर सकते हैं, और यदि कोई वैध मतदाता सूची से बाहर रह गया, तो लोकतंत्र की नींव हिल सकती है। अन्य राज्यों के अनुभव और उदाहरण हमें यह सिखाते हैं कि मतदाता सूची सिर्फ एक प्रशासनिक दस्तावेज़ नहीं, बल्कि हर नागरिक की राजनीतिक पहचान का प्रतीक है। इसलिए इसकी नियमित समीक्षा और सुधार न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से होना चाहिए। यह संशोधन दोधारी तलवार की तरह है–2.89 करोड़ नामों के हटने ने सार्वजनिक बहस और राजनीतिक विवाद को हवा दी है। यदि हटाए गए नाम केवल फर्जी थे, तो यह लोकतंत्र की शुद्धता की दिशा में ऐतिहासिक कदम होगा। लेकिन यदि वैध मतदाता प्रभावित हुए, तो यह अधिकार और विश्वास दोनों को क्षति पहुंचा सकता है। विपक्ष को ठोस प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे और आयोग को अपनी निष्पक्षता साबित करनी होगी। लोकतंत्र तब मजबूत रहेगा जब हर वैध वोट गिना जाएगा और किसी की आवाज़ दबाई नहीं जाएगी। यह प्रकरण याद दिलाता है कि वोट हमारा अधिकार है और सुरक्षित रहना चाहिए। समय ही बताएगा कि यह कदम लोकतंत्र की शुद्धता था या राजनीतिक खेल। उत्तर प्रदेश का यह उदाहरण हमें एक बड़ा और सशक्त सबक देता है। बड़े बदलाव सोच-समझकर और पूरी सावधानी के साथ होने चाहिए, क्योंकि हर गलती सीधे लोकतंत्र की नींव को हिला सकती है। जनता के लिए यह जिम्मेदारी बन गई है कि वह अपने नाम, अपने अधिकार और मतदाता रिकॉर्ड की खुद जांच करे। हर मतदाता जागरूक रहे, ताकि किसी की आवाज दबाई न जा सके और हर वैध वोट सुरक्षित रहे। चुनाव प्रक्रिया की पवित्रता पर ध्यान देना अब केवल प्रशासन का कर्तव्य नहीं, बल्कि हर नागरिक की अनिवार्य भूमिका बन चुकी है।

प्रो. आरके जैन

कड़ाके की सर्दी में इंसानियत की कसौटीरैन बसेरे

कागज़ से बड़ा जीवन, व्यवस्था से बड़ा करुणा का सवाल

कड़के की सर्दी जब अपने चरम पर होती है, जब तापमान एकल अंक में उतर जाता है और ठंडी हवाएं शरीर के आर-पार हो जाती हैं, तब सबसे बड़ा सवाल यह नहीं रह जाता कि किसी के पास कौन सा दस्तावेज है, बल्कि यह बन जाता है कि क्या वह रात सुरक्षित और गर्म जगह पर काट पाएगा या नहीं। राजस्थान के कोटा, भीलवाड़ा, जोधपुर, भरतपुर, उदयपुर और बीकानेर जैसे शहरों से सामने आई तस्वीरें बताती हैं कि रैन बसेरे इस समय जरूरतमंदों के लिए राहत का नहीं, बल्कि संघर्ष का प्रतीक बनते जा रहे हैं। कहीं रैन बसेरे खचाखच भरे हैं, कहीं ताले लटके हैं, कहीं बिस्तर टूटे पड़े हैं और कहीं सिर्फ इस वजह से लोगों को बाहर कर दिया जा रहा है कि उनके पास आधार कार्ड नहीं है। कोटा में जब तापमान 8.8 डिग्री तक पहुंच गया, तब किशोर तालाब की पाल पर बने रैन बसेरे में जगह न मिलने के कारण करीब दो दर्जन श्रमिक खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर दिखे। रिक्शा चालक धन्नालाल जैसे लोग बताते हैं कि रैन बसेरे में जगह नहीं मिलती, इसलिए पुलिया की छत के नीचे या तालाब की पाल पर ही रात गुजारनी पड़ती है। यह दृश्य सिर्फ कोटा का नहीं है। भीलवाड़ा में कई रैन बसेरों पर सुरक्षा के नाम पर ताले लटके मिले, कहीं नशेड़ियों ने डेरा डाल रखा था और वास्तविक जरूरतमंद बाहर ठंड में ठिठुरते रहे। जोधपुर में क्षमता से अधिक लोगों के आने पर एक ही बिस्तर पर दो-दो लोगों को सोते देखा गया। उदयपुर में कुछ जगह व्यवस्था बेहतर दिखी, लेकिन कई स्थानों पर पलंग टूटे हुए थे और मजदूर बस स्टैंड या दुकानों के बाहर खुले में सोने को मजबूर थे। सबसे पीड़ादायक पहलू यह है कि कई शहरों में आधार कार्ड या किसी पहचान पत्र के अभाव में लोगों को रैन बसेरे में प्रवेश नहीं दिया जा रहा। तलवंडी में महिलाएं बच्चों के साथ फ्लाईओवर के नीचे अलाव तापती दिखीं, क्योंकि उनके पास आधार कार्ड नहीं था। भरतपुर में दिव्यांग रवि कुमार और धर्मेंद्र मीणा जैसे लोगों ने बताया कि आधार कार्ड न होने की वजह से उन्हें रैन बसेरे से लौटा दिया गया। सवाल यह है कि क्या ठंड से बचने के लिए किसी दस्तावेज की अनिवार्यता इंसान की जान से बड़ी हो सकती है। जब कोई व्यक्ति फुटपाथ पर सोने को मजबूर है, तो यह साफ संकेत है कि वह पहले से ही समाज के सबसे कमजोर तबके में है। ऐसे में उससे कागज़ मांगना संवेदनहीनता की पराकाष्ठा नहीं तो और क्या है। रैन बसेरे मूल रूप से इसी सोच के साथ बनाए गए थे कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह मजदूर हो, रिक्शा चालक हो, बेसहारा बुजुर्ग हो, महिला हो या बच्चा, सर्द रात में सुरक्षित जगह पा सके। सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न सरकारी दिशानिर्देशों में भी स्पष्ट किया गया है कि आपात स्थितियों में आश्रय देने में पहचान पत्र को बाधा नहीं बनाया जाना चाहिए। इसके बावजूद जमीनी हकीकत यह है कि प्रशासनिक सुविधा और नियमों की आड़ में मानवीय संवेदना को पीछे छोड़ दिया जाता है। कागज़ों में दर्ज योजनाएं तब बेमानी हो जाती हैं, जब ठंड में कोई व्यक्ति कांपते हुए कहता है कि हमारे पास आधार कार्ड नहीं है, इसलिए हमें अंदर नहीं जाने दिया गया। यह समस्या सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं है। देश के अन्य राज्यों में भी सर्दियों के दौरान रैन बसेरों की स्थिति लगभग ऐसी ही देखने को मिलती है। दिल्ली में हर साल सर्दी बढ़ते ही फुटपाथों, बस स्टैंडों और रेलवे स्टेशनों पर सोने वालों की संख्या बढ़ जाती है। नगर निगम और राज्य सरकारें रैन बसेरे खोलने का दावा तो करती हैं, लेकिन कई बार क्षमता कम पड़ जाती है या व्यवस्थाएं नाकाफी होती हैं। उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों जैसे लखनऊ, कानपुर और वाराणसी में भी ठंड के मौसम में यह सवाल उठता रहा है कि क्या सभी जरूरतमंदों को वास्तव में आश्रय मिल पा रहा है। बिहार, मध्य प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों में भी रैन बसेरों की संख्या और गुणवत्ता को लेकर समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं। मुंबई जैसे महानगर में, जहां सर्दी राजस्थान जितनी तीखी नहीं होती, वहां भी बेघर लोगों के लिए रैन बसेरे पर्याप्त नहीं हैं। कोलकाता में भी कई सामाजिक संगठनों को आगे आकर अस्थायी आश्रय और कंबल वितरण की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, क्योंकि सरकारी व्यवस्था हर जरूरतमंद तक नहीं पहुंच पाती। यह स्थिति बताती है कि रैन बसेरा सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक सोच है, और जब तक इस सोच के केंद्र में इंसान को नहीं रखा जाएगा, तब तक समस्या बनी रहेगी। कड़के की सर्दी में व्यवस्था करना प्रशासन का दायित्व ही नहीं, बल्कि नैतिक जिम्मेदारी भी है। नगर निगम, जिला प्रशासन और राज्य सरकारें अक्सर बजट, नियम और प्रक्रिया की बात करती हैं, लेकिन सर्द रात में ठंड से कांपते व्यक्ति के लिए ये तर्क अर्थहीन हो जाते हैं। रैन बसेरों की संख्या बढ़ाना, उनकी क्षमता के अनुसार बिस्तर, कंबल, रजाई और हीटर जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना और सबसे अहम बात यह सुनिश्चित करना कि किसी भी व्यक्ति को पहचान पत्र के अभाव में बाहर न किया जाए, यह सब प्रशासन के प्राथमिक कर्तव्यों में होना चाहिए। यह भी जरूरी है कि रैन बसेरों की नियमित निगरानी हो। कई

जगह ताले लटके मिलने का अर्थ यह है कि व्यवस्था सिर्फ कागज़ों में है। कहीं निजी आश्रय स्थल पूरी तरह भरे हैं, तो सरकारी आश्रय स्थल आधे खाली पड़े हैं, यह असंतुलन भी गंभीर सवाल खड़े करता है। सुरक्षा के नाम पर आईडी जमा कराने की शर्तें तब तक ठीक लग सकती हैं, जब तक वे किसी को ठंड में मरने के लिए मजबूर न कर दें। आपात स्थिति में अस्थायी रजिस्ट्रेशन, नाम और फोटो के आधार पर भी व्यवस्था की जा सकती है। समाज के स्तर पर भी यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम इस मुद्दे को सिर्फ खबर बनकर न छोड़ दें। जिस तरह गर्मी में पानी और छांव की बात होती है, उसी तरह सर्दी में आश्रय और गर्म कपड़ों की बात होनी चाहिए। कई स्वयंसेवी संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता इस दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी पहुंच सीमित है। स्थायी समाधान तभी संभव है, जब सरकारी तंत्र पूरी संवेदनशीलता के साथ आगे आए। रैन बसेरे किसी पर एहसान नहीं हैं, बल्कि यह उस न्यूनतम मानवीय अधिकार का हिस्सा हैं, जिसके बिना सभ्य समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। जब कोई व्यक्ति कहता है कि हमारे पास आधार कार्ड नहीं है, इसलिए हमें अंदर नहीं जाने दिया गया, तो यह सिर्फ उसकी पीड़ा नहीं, बल्कि हमारी व्यवस्था की असफलता का बयान होता है। सर्द रातों में यह तय करना कि कौन दस्तावेज के योग्य है और कौन नहीं, यह इंसानियत के खिलाफ जाता है। आज जरूरत इस बात की है कि रैन बसेरों को सिर्फ एक सरकारी योजना के रूप में नहीं, बल्कि मानवीय संवेदना के प्रतीक के रूप में देखा जाए। चाहे राजस्थान हो या कोई अन्य राज्य, चाहे महानगर हो या छोटा शहर, सर्दी सबके लिए एक जैसी होती है। ठंड यह नहीं पूछती कि आपके पास आधार कार्ड है या नहीं। ऐसे में प्रशासन और समाज को भी यह सवाल छोड़ देना चाहिए। एक बार इंसानियत के नाते, बिना किसी शर्त के, हर जरूरतमंद को रैन बसेरे में जगह दी जानी चाहिए। यही किसी भी सभ्य और संवेदनशील समाज की असली पहचान है।

कांतिलाल मांडोत

स्वामी- स्वतंत्र प्रभात मीडिया, मुद्रक एवं प्रकाशक प्रीती शुक्ला द्वारा सुशीला स्टेडी बेल एकेडमी 117-मोहल्ला बिजय लक्ष्मी नगर परगना सौराचाद तहसील व जनपद सीतापुर से प्रकाशित तथा महावीर आफसेट 28, होनेट रोड लखनऊ से मुद्रित। सम्पादक रवि कुमार अवस्थी समाचार पत्र में तमे समस्त समाचार संवाददाताओं के अपने श्रोत एवं संकलन हैं, जिनसे सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। **नोटः** उपरोक्त सभी पद अवैतनिक एवं स्वयंसेवी हैं तथा समाचार पत्र से सम्बंधित सारे विवादों का न्याय क्षेत्र सीतापुर होगा। R.NI NO. UPHIN/2012/43078 मो0 नं0-9511151254, E-Mail: news@swatantraprabhat.com

संक्षिप्त खबरें

भावना संस्था द्वारा कम्बल वितरण आयोजन संपन्न

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में आज दिनांक 7 जनवरी 2026 को भारतीय वरिष्ठ नागरिक समिति भावना के ग्रामांचल निर्धन जन सेवा प्रकोष्ठ द्वारा गायत्री शक्तिपीठ, रामपुर-देवराई, बी0के0टी0, लखनऊ परिसर में गरीबों को ऊनी कम्बल प्रदान करने का कार्यक्रम आयोजित हुआ। भावना द्वारा 100 ग्रामीण सुपात्र लाभार्थियों को ऊनी कम्बल वितरित किए गए। कम्बल वितरण के पश्चात लाभार्थियों एवं सभी उपस्थित जन को गायत्री परिवार की व्यवस्था तंत्र द्वारा माता जी का प्रसाद अमृताशन भोज उपलब्ध कराया गया। इस अवसर पर भावना के प्रमुख सचिव एस0के0 वर्मा, महासचिव जगमोहन लाल जायसवाल, प्रकोष्ठ संयोजक अमर नाथ धवन, आर0डी0 स्वर्णकार, ए0पी0 सिंह, अनिल खन्ना, डॉ0 शुक्ला, आई0के0 भारद्वाज, एम0एल0 अग्रवाल, भारत भूषण गोयल, अखिल कुमार गुप्ता, जायसवाल, नीना अग्रवाल, अग्रवाल सहित कई अन्य पदाधिकारी गण तथा गायत्री परिसर व्यवस्था की ओर से पुनीत खरे, एस0आर0 सिंह, पवन मिश्र, अर्जुन सिंह, नरेंद्र सिंह आदि उपस्थित रहे।

अज्ञात वाहन की चपेट में आकर भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष की दर्दनाक मौत

बिसवां सीतापुर बिसवां देहात अज्ञात वाहन की चपेट में आकर भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शव पीएम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है। कोतवाली बिसवां इलाके के अमझला नहर के पास सड़क दुर्घटना में अज्ञात वाहन की चपेट में आकर एक युवक की मौत हो गई। बताया जाता है कि युवक बिसवां से अपने घर जा रहा था। इसी दौरान सरायं-सकरापुर मार्ग पर अज्ञात परिस्थितियों में सड़क हादसा हो गया, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान भाजपा मंडल उपाध्यक्ष मानपुर अजीत शुक्ला, निवासी भुइलाकलां के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार अजीत किसी निजी कार्य से बिसवां आए हुए थे। और देर शाम घर लौटते समय यह हादसा हुआ। परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। मृतक के पत्नी सहित छोटे छोटे दो बच्चे हैं। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई, इसकी जांच-पड़ताल की जा रही है।

पत्रकार ने अपनी माता की पुण्यतिथि पर मरीजों में वितरित किया पूड़ी सब्जी व फल

डलमऊ रायबरेली पत्रकार बृजेंद्र कुमार ने बुधवार को अपनी माता संपत्ति देवी पत्नी हरिशंकर की 19वीं पुण्यतिथि के अवसर पर परिवारिक जनों के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डलमऊ पहुंचकर वहां पर भर्ती मरीजों एवं तीमारदारों को पूड़ी सब्जी,बिस्किट,फल आदि वितरित किया। पत्रकार बृजेंद्र कुमार एवं उनके बड़े भाई सुशील कुमार ने बताया कि जरूरतमंदों गरीबों एवं मरीजों की सेवा करना ही सबसे बड़ी सेवा है। अवसर बनाकर मजलूमों जरूरतमंदों की सेवा करना ही अपने पूर्वजों की सच्ची श्रद्धांजलि होती हैमाता की प्रेरणा से ही वह पिछले 18 वर्षों से पुण्यतिथि को अवसर बनाकर गरीबों,मरीजों एवं जरूरतमंदों के चेहरे पर मुस्कान लाने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं इससे हम सभी को परम सुख की प्राप्ति होती है। इस अवसर पर सुशील कुमार, सुधीर कुमार, अरविंद कुमार, गुड्डू जायसवाल, दीपक कुमार, मनोज सोनकर एवं पारिवारिजन मौजूद रहे।

लोकप्रिय सांसद राहुल गांधी द्वारा भेजे गए कंबल जरूरतमंद लोगों को कांग्रेसियों ने किया वितरित

महराजगंज रायबरेली। रायबरेली के लोकप्रिय सांसद राहुल गांधी द्वारा क्षेत्र के जरूरतमंद लोगों के लिए भेजे गए कंबलों का वितरण बुधवार को ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय महराजगंज में किया गया।कार्यक्रम का आयोजन ब्लॉक अध्यक्ष सच्चिदानंद त्रिपाठी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं की उपस्थिति में कंबल वितरण सम्पन्न हुआ। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सुशील पासी, कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष मो. इलियास और पीसीसी सदस्य प्रदीप चौधरी ने क्षेत्र के आए निराश्रितों को कम्बल वितरित किए। कांग्रेसियों ने राहुल गांधी के इस सेवा भाव की सराहना करते हुए कहा कि जननायक सदैव गरीबों और वंचितों के हितों के लिए तत्पर रहते हैं। कड़ाके की इस ठंड में कंबलों का वितरण एक सराहनीय मानवीय प्रयास है। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कृपाशंकर शर्मा, पीसीसी सदस्य, अंकुर जायसवाल, नगर कांग्रेस अध्यक्ष, रामशरण शुक्ल एवं भगवान दीन फौजी, रविचंद्र सिंह, हौसला तिवारी (मंडल अध्यक्ष), गयाप्रसाद चौरसिया (मंडल अध्यक्ष) समेत समस्त न्याय पंचायत अध्यक्ष व ग्राम सभा अध्यक्ष और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी व कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

ग्राम पंचायत गुरेरा में दबंगों ने बंजर भूमि और चक मार्ग पर किया कब्जा

● ग्रामीणों ने उपजिलाधिकारी से की कार्रवाई की मांग

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बिसवां (सीतापुर)। ग्राम पंचायत गुरेरा में ग्राम प्रधान और ग्रामीणों ने जमाल खां आदि के द्वारा बंजर भूमि और चक मार्ग पर अवैध कब्जा किए जाने के खिलाफ उपजिलाधिकारी से त्वरित कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने गाटा संख्या 1163 (चकमार्ग) और 1164(बी) बंजर भूमि को लेकर प्रार्थना पत्र सौंपा है। ग्रामीणों के अनुसार, जमाल खां ने चक मार्ग पर खंभा और निर्माण कर स्थायी अवरोध स्थापित कर दिया है, जिससे रास्ता पूरी तरह बंद हो गया है और स्थानीय लोगों को आवागमन में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ग्राम प्रधान ने बताया कि पहले भी लेखपाल, कानूनगो और अन्य अधिकारियों को मामले की जानकारी दी गई थी, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। इससे अवैध कब्जा धारियों के हौसले और बढ़ गए हैं। ग्राम प्रधान और ग्रामीणों ने उपजिलाधिकारी से अनुरोध किया है कि अविलंब अवैध कब्जा हटाकर चक मार्ग को खुलवाया जाए, ताकि ग्रामवासियों का दैनिक जीवन सुचारू रूप से चल सके।

गुरु गोविंद सिंह प्रकाश पर्व के अवसर पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा

बिसवां सीतापुर गुरु गोविंद सिंह प्रकाश पर्व पर बिसवां कस्बे में सिख समुदाय द्वारा भव्य शोभायात्रा गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा के तत्वावधान मे अरदास के बाद निकाली गई जो कस्बे में भ्रमण करती हुई गुरु तेज बहादुर गुरुद्वारा होते हुए मंगरैया बाजार सब्जी मंडी बड़ा चौराहा रायगंज होते हुए पुनः गुरुद्वारा पुरवारी टोला पर समाप्त हुई ।शोभायात्रा में सिख समुदाय की महिलाएं आगे-आगे झाड़ू लगाते चल रही थी। वहीं भारी संख्या में महिलाएं पुरुष व बच्चे शामिल थे ।बच्चों द्वारा शोभायात्रा में बहुत ही सुंदर प्रदर्शन किया जा रहा था। जगह-जगह पर लोगों द्वारा फूलों की वर्षा की गई। इसके बाद गुरुद्वारे में लंगर का आयोजन हुआ ।सुरक्षा की दृष्टिकोण से भारी संख्या में पुलिस दल भी साथ-साथ चल रहा था ।इस अवसर पर मुख्य रूप से गुरु सिंह सभा अध्यक्ष भजनसिंह सचदेवा चरणजीत सिंह सुरेन्द्र पाल सिंह, हरजीत सिंह,इंद्रपाल सिंह महेंद्र सिंह इंद्रजीत सिंह चरणजीत सिंह, सोनू सिंह,गगन सिंह मनजीत सिंह सहित भारी संख्या में सिख समुदाय के लोग मौजूद रहे।

विकासखंड मिश्रिख के पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने मनाया नव वर्ष

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

मिश्रिख (सीतापुर) उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ विकासखंड मिश्रित व्दारा नव वर्ष 2026 के शुभ अवसर पर आज विकासखंड के बैठक हाल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में खंडविकास अधिकारी सुनील कुमार कौशल , सहायक विकास अधिकारी पंचायत तथा समस्त ग्राम पंचायत सचिव एवं स्थानीय पत्रकार अतिथिगणो को नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभ कामनाए दी। तथा सभी सफाई कर्मचारियों को डायरी देकर सम्मानित किया। इस मौके पर सभी अतिथियों का पुष्प मालाओं, मिठाई एवं डायरी भेंट करके स्वागत किया गया। सभी कर्मचारियों ने संघ की एकता एवं संगठन की मजबूती का संकल्प भी दोहराया। इस अवसर पर विकासखंड के सफाई कर्मचारी संघ के पदाधिकारी ब्लाक अध्यक्ष मनोज कुमार, ब्लाक कोषाध्यक्ष रामलोटन, संघ महामंत्री ऊदन कुमार, संगठन मंत्री कुलदीप कुमार, संप्रेक्षक पूनम देवी, उपाध्यक्ष अरविंद कुमार वर्मा सहित सभी सफाई कर्मचारी उपस्थित रहे।

एडवोकेट अमृता सिंह ने बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के प्रत्याशी प्रदीप कुमार सिंह की जीत के लिए पत्थर शिवाला मंदिर में की पूजा अर्चना

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बिसवा (सीतापुर) हाई कोर्ट लखनऊ की वरिष्ठ अधिवक्ता अमृता सिंह ने अधिवक्ता समर्थकों के साथ बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के प्रत्याशी बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश प्रदीप कुमार सिंह की आगामी चुनाव में जीत के लिए तहसील बिसवा के प्रसिद्ध व प्राचीन पत्थर शिवाला मंदिर में जाकर भोलेनाथ शिव जी के दरबार में माथा टेक कर विधिवत की पूजा अर्चना। वरिष्ठ अधिवक्ता हाई कोर्ट लखनऊ अमृता सिंह ने बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के प्रत्याशी प्रदीप कुमार सिंह के चुनाव के मद्देनजर तहसील बिसवा,लहरपुर में भ्रमण कर सहयोग की अपील की।

वरिष्ठ अधिवक्ता अमृता सिंह अपने अधिवक्ता समर्थकों शुभी सोनी सिंह,रीता शर्मा,विशाल सिंह,जगलाल राजपूत के साथ नगर के प्रसिद्ध व प्राचीन पत्थर शिवाला मंदिर पहुंची,वहां पर भोलनाथ शिव जी के दर्शन कर पूजा अर्चना की,एवं मंदिर में सभी दरबार में स्थापित भगवान की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर बिसवा बार एसोसिएशन बिसवा के अध्यक्ष दिनेश कुमार श्रीवास्तव, अधिवक्ता नीरज कुमार श्रीवास्तव, प्रीती श्रीवास्तव अधिवक्ता गण साथ में रहे।

ककराही रेलवे फाटक के पास सड़क हादसा

दुर्घटना/हादसा

गोपीगंज। कोतवाली क्षेत्र के ककराही रेलवे फाटक के पास मंगलवार देर शाम अज्ञात चार पहिया वाहन की टक्कर से बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। गल्हैया ज्ञानपुर निवासी शिवम (22) पुत्र अमृतलाल मौर्य और प्रमोद गिरी (23) पुत्र कैलाश गिरी बाइक से घर लौट रहे थे, तभी पीछे से आए वाहन ने टक्कर मार दी। सूचना पर 108 एंबुलेंस से घायलों को सीएचसी गोपीगंज लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। हादसे के बाद वाहन चालक फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

सकल हिंदू समाज आयोजक समिति द्वारा हिंदू सम्मेलन का किया गया आयोजन

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बिसवां सीतापुर बिसवां कस्बे के सरस्वती शिशु मंदिर पुरवारी टोला में मंगलवार को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के नेत्रत्व में सकल हिन्दू समाज आयोजक समिति द्वारा केशव बस्ती में हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता जय प्रकाश क्षेत्र व्यवस्था प्रमुख एवं वरिष्ठ प्रचारक ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हिन्दू सम्मेलनों में सकल हिन्दू समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा मिलकर किया जा रहा है जिससे समाज के समस्त अंगों में आपस में भाईचारा पुष्ट हो रहा है। छोटे छोटे आपसी मतभेद समाप्त हो रहे हैं एवं विशेष रूप से युवा नागरिकों को हिंदू सनातन संस्कृति के संस्कारों से अवगत होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इन हिन्दू सम्मेलनों के आयोजन का उद्देश्य भी सनातन संस्कृति, सनातन धर्म और सामाजिक एकता को सुदृढ़ करना है, जिसकी प्राप्ति होती हुई दिख रही है। भारत के भी आज विश्व के लगभग समस्त देशों के साथ दोस्ताना सम्बंध हैं, भारत ने कभी भी किसी देश की जमीन पर कब्जा करने के उद्देश्य से किसी देश के साथ युद्ध नहीं किया है। भारत सदैव से ही 'जियो और जीने दो' के सिद्धांत का अनुपालन करता आया है। बल्कि, विश्व के अन्य देशों के नागरिक, जैसे, शक, हूण, कुषाण, पारसी, यहूदी, ईसाई एवं मुस्लिम भी भारत आकर आसानी से यहां रच बस गए हैं। आज पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें मुस्लिम समाज के समस्त फिर्के पाए जाते हैं। संत रघुवंश शास्त्री ने कहा कि हिंदुत्व यदि सशक्त होता है तो यह न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के हित में होगा क्योंकि आज विश्व के विभिन्न देशों में फैली अशांति को दूर करने में केवल सनातन हिंदू संस्कृति ही सक्षम दिखाई दे रही है और इस विषय को विभिन्न देशों में फैले भारतीय मूल के नागरिकों के माध्यम

से विकसित एवं अन्य देशों के नागरिक भलीभांति समझने लगे हैं क्योंकि इन देशों में निवासरत भारतीय मूल के नागरिक सनातन हिंदू संस्कृति के संस्कारों का अनुपालन करते हुए दिखाई देते हैं जिनमें 'वसुधैव कुटुम्बकम' का भाव दिखाई देता है। इन देशों में समस्त भारतीय मूल के नागरिक शांतिपूर्वक अपना जीवन यापन करते हैं एवं वहां की स्थानीय अर्थव्यवस्था में अपना सशक्त योगदान देते हुए दिखाई देते हैं। कार्यक्रम का सफल संचालन साहित्यकार आनंद खत्री ने किया ढ्ढ इस अवसर पर सैकड़ों हिंदू जन एकत्र हुए।

विद्यांत शिक्षण संस्थान में संस्थापक दिवस समारोह होनहार विद्यार्थियों को विद्यांत मेडल पुरस्कार

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। राजधानी लखनऊ के विद्यांत हिंदू पीजी कॉलेज, विद्यांत इंटर कॉलेज एवं विद्यांत प्राइमरी विद्यालय में संस्थापक दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस शिक्षण संस्थान के संस्थापक प्रबंधक विक्टर नारायण विद्यांत की जयंती को संस्थापक दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर होनहार विद्यार्थियों को विद्यांत मेडल से पुरस्कृत किया गया इसके साथ ही साथ महाविद्यालय वार्षिक पत्रिका साक्षी का भी लोकार्पण किया गया मुख्य अतिथि राज्य सूचना आयुक्त डॉ0 दिलीप अग्निहोत्री ने कहा कि बी0एन0 विद्यांत जी के जीवन से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है उन्होंने समाज में अपनी संपदा दान कर दी थी यह समाज और राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण भाव था। विद्यांत एजुकेशनल ट्रस्ट के प्रबंधक शिवशीष घोष ने समाज के सभी वर्गों को शिक्षा प्रदान करके महाविद्यालय की भूमिका पर प्रकाश डाला। सहायक प्रबंधक अविक भट्टाचार्य ने सुलभ शिक्षा को आकार देने में संस्थापक की विरासत को रेखांकित किया। प्राचार्य प्रो0 धर्म कौर ने शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक क्षेत्र में छात्रों के प्रदर्शन को एक मूल परंपरा बताया। प्रो0 राजीव शुक्ला ने इस कार्यक्रम को शैक्षणिक योग्यता और सांस्कृतिक मूल्य को सम्मानित करने मंच बताया। विक्टर नरायण विद्यंत ने 1938 में नवाब अमजद अली शाह के वित्त मंत्री राजा दक्षिण रंजन मुखर्जी के वंशजों से खरीदी गई भूमि पर इस संस्थान की स्थापना की थी। यह संस्थान 1944 में हाई स्कूल और 1946 में इंटरमीडिएट कॉलेज के रूप में विकसित हुआ लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्धता के तहत 1954 में बी0ए0 पाठ्यक्रम शुरू हुआ। इसके बाद 1974 में बी0कॉम0 शुरू हुआ स्नातकोत्तर कार्यक्रम 2006 में शुरू किया गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्ति कॉलेज शहर में एक शैक्षणिक केंद्र के

रूप में कार्य करता है। शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के अंतिम वर्ष के लखनऊ विश्वविद्यालय की परीक्षा के परिणाम के आधार पर प्रत्येक पाठ्यक्रम में शीर्ष तीन छात्रों को पुरस्कार दिए गए। विपुल श्रीवास्तव प्रथम, आदित्य यादव द्वितीय, अनामिका तिवारी तृतीय स्थान प्राप्त किया। बी0 ए0 मेंकल शर्मा प्रथम, सचिन शुक्ला द्वितीय, राहुल सिंह तृतीय स्थान प्राप्त किया। बी0 कॉम0 अनुज प्रथम, अभिजीत सावरनी द्वितीय, सौर्य निगम तृतीया एम0 कॉम0 प्रीति त्रिपाठी प्रथम, इसाम मुस्तकीम द्वितीय, मानसी सिंह तृतीय शामिल रहे।

क्षेत्र के हिलहा गांव में घर में घुसे अज्ञात बदमाशों ने गृह स्वामी किसान पर चाकूओं से किया हमला

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

महराजगंज/रायबरेली। घर में घुसे अज्ञात बदमाशों ने गृह स्वामी किसान पर चाकूओं से हमला कर दिया। व उसकी पत्नी से भी मारपीट कर घायल कर दिया।शोर सुनकर लोगों के आने की आहट पाकर अज्ञात बदमाश फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की छानबीन शुरू कर दी है। वही घायल किसान गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती है।

क्षेत्र के हिलहा गांव निवासी किसान पवन बाजपेई 52 वर्ष अपनी पत्नी व दो बच्चों के साथ घर के आंगन में बने बरामदे में सो रहे थे। रात करीब एक बजे छत के रास्ते घर में घुसे अज्ञात बदमाशों की चहलकदमी से उनकी पत्नी रिंकी की नींद खुली तो उन्होंने आंगन में दो लोगों को उनके पति पर हमला करते देख सहम गई। उन्होंने छुपकर प्रधान प्रतिनिधि दिलीप तिवारी को फोन कर जानकारी दी। तभी दरवाजे में लगे परदे के पीछे छिपे एक बदमाश ने उनका गला दबा दिया। चीख-पुकार सुनकर पड़ोसी पहुंचते तब तक बदमाश फरार हो गए। सूचना पर पहुंची डायल पुलिस व कोतवाली पुलिस ने रात में ही छानबीन शुरू कर दी है। घटना में किसान के चेहरे व पेट में चाकुओं के कई गहरे घाव हैं। घायल किसान पवन बाजपेई को डायल पुलिस व प्रधान प्रतिनिधि दिलीप तिवारी ने सीएचसी

पहुंचाया जहां से चिकित्सकों ने उन्हें गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर कर दिया। घटना के बाबत कोतवाल जगदीश यादव ने बताया कि जमीनी विवाद की रंजिश के चलते किसान पर हमला हुआ है। अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है। जल्द ही गिरफ्तार कर कार्यवाही की जाएगी। क्षेत्राधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया पुरानी रंजिश को लेकर हमले की बात सामने आ रही है। फारेंसिक टीम बुलाई गई है। घटना के सभी पहलुओं की छानबीन की जा रही है। जल्द ही आरोपियों की शिनाख्त कर कार्यवाही की जाएगी।

पड़ोसी श्याम तिवारी, दिलीप तिवारी आदि अन्य ग्रामीणों का कहना है कि चोरी की नियत से घर में घुसे बदमाशों ने दम्पति के जाग जाने से उन पर जानलेवा हमला कर दिया। जबकि किसान के साथ जिला अस्पताल में मौजूद परिजन विमल किशोर अवस्थी का कहना है कि पुरानी रंजिश को लेकर उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया है।

नशे में धुत चालक बस सड़क किनारे रोकी, यात्रियों में मचा हड़कंप

नशे में झूमता रहा बस चालक,यात्री रहे परेशान

लालगंज (रायबरेली)। कस्बे के बाईपास रोड पर बुधवार को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की एक बस में उस समय हंगामा मच गया, जब बस चालक नशे की हालत में पाया गया। आलमबाग डिपो की यह बस फतेहपुर से यात्रियों को लेकर लखनऊ जा रही थी। बताया गया कि बाईपास रोड पर पहुंचते ही चालक ने बस को अनियंत्रित ढंग से चलाना शुरू कर दिया, जिससे बस में बैठे यात्री सहम गए। कुछ यात्रियों ने विरोध किया तो चालक और परिचालक के बीच बहस शुरू हो गई। नशे में धुत चालक ने बस आगे ले जाने से इनकार कर दिया और सड़क किनारे बस खड़ी कर दी। इसके बाद वह बस में ही लेट गया। घटना के दौरान बस में बैठे यात्रियों, खासकर महिलाओं और बुजुर्गों में भय का माहौल बन गया। रालपुर निवासी पंकज ने बताया कि उन्हें लखनऊ जाना था, लेकिन चालक काफी देर तक बस नहीं चला रहा था। नगर निवासी विनीता ने आरोप लगाया कि चालक नशे में यात्रियों और परिचालक से उलझ रहा था। स्थिति को संभालते हुए परिचालक ने सूझबूझ दिखाई और यात्रियों को दूसरी बस में शिफ्ट कराया। इसके बाद सभी यात्रियों को उनके गंतव्य की ओर रवाना किया गया। हालांकि, इस दौरान यात्रियों को काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। कुछ यात्री बस से उतरकर वैकल्पिक साधन तलाशते भी नजर आए। सड़क किनारे खड़ी सरकारी बस काफी देर तक लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रही।

कड़ाके की ठंड में, 30 जरूरतमंदों को बांटे गए कंबल

कंबल पाकर लाभार्थियों के खिले चेहरे

स्वतंत्र प्रभात
ब्रेकिंग न्यूज़

लालगंज (रायबरेली)। भीषण ठंड को देखते हुए बुधवार को ब्लॉक कार्यालय परिसर में जरूरतमंदों के लिए कंबल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान चकपंचम व चांदा बन्नामऊ गांव के कुल 30 असहाय व गरीब लोगों को गर्म कंबल वितरित किए गए। कंबल पाकर लाभार्थियों के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दी। कार्यक्रम में खंड विकास अधिकारी गगनदीप सिंह ने स्वयं जरूरतमंदों को कंबल प्रदान किए। उन्होंने कहा कि ठंड के मौसम में गरीब व असहाय लोगों की मदद करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। आगे भी इसी तरह के राहत कार्य लगातार जारी रहेंगे।

खंड विकास अधिकारी ने लोगों से ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़ों के प्रयोग की अपील करते हुए समाज से जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आने का आह्वान किया।

इस अवसर पर समाजसेवी मुन्ना सिंह चौहान, एडीओ पंचायत प्रणवीर प्रताप सिंह, सूरह आलम, सुचित कुमार, सीमा मौर्य और पूनम यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

अगर आप चाहें तो मैं अखबार के कॉलम साइज, डिजिटल पोर्टल, या सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार भी इसे ढाल सकता हूँ।

बरौली प्रखंड कार्यालय में आयोजित हुआ 'प्रशासन जनता के द्वार' कार्यक्रम

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

गोपालगंज (बिहार)- जिला पदाधिकारी गोपालगंज द्वारा बरौली प्रखंड कार्यालय परिसर में प्रशासन जनता के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस जनोपयोगी कार्यक्रम का उद्देश्य प्रशासन को सीधे आम जनता से जोड़ना तथा उनकी समस्याओं का त्वरित एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना रहा। कार्यक्रम का उद्घाटन बरौली विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक मनजीत सिंह एवं जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों–जैसे राजस्व, कृषि, आपूर्ति, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनरेगा, जीविका, पंचायती राज, विद्युत, परिवहन सहित अन्य विभागों–द्वारा अलग-अलग स्टॉल लगाए गए। इन स्टॉलों पर उपस्थित पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों ने आम नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और मौके पर ही कई मामलों का निराकरण किया गया। जिन मामलों का त्वरित समाधान संभव नहीं था, उन्हें संबंधित विभागों को अग्रसारित करते हुए समयबद्ध निष्पादन के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में बरौली प्रखंड के ग्रामीण नागरिक उपस्थित रहे। ग्रामीणों ने भूमि विवाद, राशन कार्ड, पेंशन, आवास योजना, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं, बिजली एवं अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित अपनी समस्याओं के समाधान हेतु जिला पदाधिकारी को आवेदन भी सौंपे। जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने प्राप्त आवेदनों पर शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया तथा संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनता की समस्याओं का समाधान सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ किया जाए।

कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त कुमार विवेक निशांत, अनुमंडल पदाधिकारी गोपालगंज अनिल कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी संदीप कुमार सहित सभी विभागों के वरीय पदाधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण कर कार्यप्रणाली की समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस अवसर पर विधायक मनजीत सिंह ने कहा कि *प्रशासन जनता के द्वार* जैसे कार्यक्रमों से आम लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जिला मुख्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, बल्कि प्रशासन स्वयं जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान करता है। उन्होंने इस पहल की सराहना करते हुए इसे जनहित में एक सराहनीय कदम बताया। कार्यक्रम का समापन सकारात्मक माहौल में हुआ। उपस्थित ग्रामीणों ने जिला प्रशासन द्वारा आयोजित इस पहल की सराहना की और उम्मीद जताई कि ऐसे कार्यक्रम भविष्य में भी निरंतर आयोजित किए जाएंगे, जिससे प्रशासन और जनता के बीच विश्वास एवं संवाद और मजबूत हो सके।

जनवरी में पूरी की जाए जल जीवन मिशन के तहत जलापूर्ति- जिलाधिकारी

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

उरई(जालौन): जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने कलेक्ट्रेट सभागार में जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल योजना की प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए कहा कि पेयजल आपूर्ति में किसी भी प्रकार की लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों और कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया है कि अवशेष कार्यों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण कर आमजन को निर्बाध पेयजल उपलब्ध कराया जाए।

समीक्षा के दौरान अवगत कराया गया कि योजना के अंतर्गत जनपद में लगभग 1600 किलोमीटर सड़कों की खुदाई की गई थी, जिनमें से 1260 किलोमीटर सड़कों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। जांच में यह भी सामने आया कि 264 ग्राम पंचायतों में लगभग 330 किलोमीटर सड़क निर्माण अभी अवशेष है। इस पर जिलाधिकारी ने कार्यदायी एजेंसियों जीवीपीआर एवं बीजीसीसी को निर्देश दिए कि 31 जनवरी तक प्रत्येक ग्राम पंचायत में सड़क पुनर्निर्माण का कार्य अनिवार्य रूप से पूरा किया जाए। बैठक में विभिन्न स्थानों पर निर्माण कार्यों के दौरान क्षतिग्रस्त पाइपलाइनों के कारण कई ग्रामों में पिछले चार माह से बाधित जलापूर्ति को लेकर जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग और संबंधित निर्माण खंडों को निर्देश दिए कि ग्राम कुरकुरू, करथरा, गुढ़ा, सिमरिया, टीहर, धन्जा एवं गिरथान सहित सभी प्रभावित गांवों में क्षतिग्रस्त पाइपलाइनों को जनवरी माह के भीतर दुरुस्त कर जलापूर्ति सुनिश्चित कराएं।

जिलाधिकारी ने कहा कि पुलिया एवं कल्वर्ट निर्माण के दौरान पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, इसलिए भविष्य में ऐसे निर्माण कार्यों के प्राक्कलन में पाइपलाइन शिफ्टिंग को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा किसी भी खुदाई कार्य से पूर्व प्रतिदिन व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से वर्क प्लान साझा किया जाए जिससे आपसी समन्वय स्थापित कर नुकसान से बचा जा सके। विद्युत आपूर्ति संबंधी समस्याओं पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि कोटा मुस्तकिल पेयजल योजना के अंतर्गत इंटेकवेल एवं जल शोधन संयंत्र को स्वतंत्र फीडर से जोड़ा जाना आवश्यक

है ताकि लो वोल्टेज की समस्या समाप्त हो सके। सहाव, धनौरा कलां, सरावन, सारंगपुर, मिझौना, सिंगपुरा एवं चतेला नलकूप पेयजल योजनाओं में स्थापित ट्रांसफॉर्मरों पर दो दिन के भीतर विद्युत आपूर्ति प्रारंभ कराने के निर्देश भी उन्होंने दिए। जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्थाओं को चेतावनी देते हुए कहा कि मैनपॉवर बढ़ाकर सड़क पुनर्निर्माण, पाइपलाइन मरम्मत और जलापूर्ति कार्यों में तेजी लाई जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि हर घर जल योजना सरकार की प्राथमिकता है और इसमें किसी भी स्तर पर शिथिलता मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में अधिशाषी अभियंता नमामि गंगे ग्रामीण अंचल गुप्ता, जिला पंचायत राज अधिकारी राम अयोध्या प्रसाद सहित सम्बंधित अधिकारी मौजूद रहे।

संक्षिप्त खबरें

पीड़िता के बयान के बाद दुष्कर्म का दूसरा आरोपी भी गिरफ्तार

हमीरपुरः– बीते 31 दिसंबर को सुमेरपुर कस्बा के रविंद्र कुमार भारतवंशी के खिलाफ 4 वर्ष तक दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज कराने वाली महिला ने अदालत में बयान के दौरान कस्बे के एक और युवक पर भारतवंशी के इशारे पर दुष्कर्म करने का बयान दर्ज कराया है। अदालत में हुये बयान के बाद पुलिस ने दूसरी युवक को भी गिरफ्तार करके जेल भेजा है। कस्बे की एक महिला ने 31 दिसंबर को मुकदमा दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि उसको खाना बनाने के लिए घर पर रखने वाले रविंद्र कुमार भारतवंशी ने डरा धमकाकर चार वर्ष तक दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो आदि बना लिए थे। साथ ही गुजारा भत्ता देने का लालच देकर लगातार संबंध बनाता रहा। बाद में अपने वायदे से मुकर गया है। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर रविन्द्र कुमार भारतवंशी के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। पीड़िता ने अदालत में बयान के दौरान आरोप लगाया था कि उसके साथ रविन्द्र कुमार भारतवंशी के इशारे पर कस्बे के प्रत्यूश साहू ने भी दुष्कर्म किया था। अदालत में दर्ज कराए गए बयान के बाद पुलिस ने प्रत्यूष साहू को मुकदमे में आरोपी बनाकर गिरफ्तार करके जेल भेजा है। यह प्रकरण कस्बे में चर्चा का विषय बना हुआ है। थानाध्यक्ष अनूप सिंह ने बताया कि अदालत में पीड़िता ने प्रत्यूश साहू पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था इसलिए उसे आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया गया है।

एसडीएम ने किया नगरपालिका गौशाला का औचक निरीक्षण

हमीरपुरः– शीतलहर और कड़ाके की ठंड के बीच राठ नगरपालिका स्थित गौशाला का उपजिलाधिकारी अभिमन्यु कुमार ने औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान क्षेत्राधिकारी, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने गौशाला में मौजूद सुविधाओं, साफ-सफाई और पशुओं के ठंड से बचाव के इंतजामों का बारीकी से जायजा लिया। निरीक्षण के समय गौवंशों को गुड़ व अजवाइन खिलाकर उनके स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति देखी गई। एसडीएम ने पशुओं को ठंड से सुरक्षित रखने के लिए अलाव की व्यवस्था, पर्याप्त भूसे की उपलब्धता, स्वच्छ पेयजल और नियमित पशु चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि गौवंशों के संरक्षण और देखभाल में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही प्रशासन द्वारा गौशाला में तैनात कर्मचारियों, सड़क किनारे बसे निराश्रित परिवारों एवं जरूरतमंद लोगों को ठंड से बचाव हेतु कंबल वितरित किए गए। एसडीएम ने कहा कि शीतलहर के इस दौर में प्रशासन की प्राथमिकता है कि कोई भी व्यक्ति या पशु ठंड के कारण असुविधा का शिकार न हो। उपजिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को नियमित निरीक्षण करने और व्यवस्थाओं की सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो जिम्मेदारों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की इस सक्रिय पहल से गौवंशों के संरक्षण के साथ-साथ जरूरतमंद लोगों को भी राहत मिली है।

तेज रफ्तार कार की टक्कर से महिला की मौत, 2 घायल

उरई(जालौन): कोतवाली क्षेत्र में मंगलवार देर रात हुए सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग घायल हो गए। हादसा उरई-कालपी मार्ग पर राहिया गांव के पास हुआ जहां तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़ी महिला को टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल महिला को तत्काल उरई के राजकीय मेडिकल कॉलेज ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका की पहचान राहिया गांव निवासी 45 वर्षीय रमा पत्नी योगेंद्र सिंह पाल के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार, रमा किसी कार्य से सड़क किनारे खड़ी थीं तभी उरई से कालपी की ओर जा रही एक अनियंत्रित कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। मृतका के पति योगेंद्र सिंह पाल ने आरोप लगाया है कि कार चालक नशे की हालत में था। उन्होंने बताया कि उसी कार ने उनकी पत्नी के अलावा दो अन्य लोगों को भी टक्कर मारी, जिससे उक्त दोनों घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही उरई कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त वाहन को कब्जे में लेकर चालक को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल पुलिस चालक से पूछताछ कर रही है, साथ ही उसके नशे में होने की पुष्टि के लिए चिकित्सीय जांच कराई जा रही है।

शासन की मंशा के विरुद्ध संचालित के मौदहा कस्बा में अवैध आटो स्टैंड, स्थानीय प्रशासन बना मूक दर्शक

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

हमीरपुरः– मौदहा कस्बा में लगभग एक दर्जन से अधिक अवैध आटो स्टैंड संचालित हो रहे हैं। जहां सुबह से शाम तक दर्जनों आटो गाड़ियों की क़तार लगी रहती है और इससे लगने वाले जाम से कस्बा की ट्रैफिक व्यवस्था चौपट रहती है। इसके बावजूद अवैध वसूली का केंद्र बने ये अवैध आटो स्टैंड फल-फूल रहे हैं। ऐसे में आम जनमानस में एक ही चर्चा है कि आखिर कौन चला रहा है कस्बा के अवैध आटो स्टैंड?

बताते चलें कि मौदहा कस्बा में एक दर्जन से अधिक अवैध आटो स्टैंड संचालित हो रहे हैं। इनमे से अरतरा चौराहा,गुड़ाही बाजार, रहमानिया रोड, मली कुआं चौराहा एवं बड़ा चौराहा में संचालित अवैध आटो स्टैंड मुख्य हैं।इनके अलावा अन्य कई स्थानों पर भी अवैध रूप से आटो स्टैंड संचालित हो रहे हैं। जबकि सरकार द्वारा इन अवैध स्टैंड पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। इसके बावजूद कस्बा में संचालित हो रहे ये अवैध आटो स्टैंड निश्चित रूप से सरकारी आदेश को खुली चुनौती दे रहे हैं। लोगों की मानें तो ये आटो स्टैंड स्थानीय पुलिस और प्रशासन के द्वारा संचालित हो रहे हैं। जिनसे अच्छी खासी कमाई की जाती है और इस अवैध धन का बंदरबांट होता है। जिसमें छोटे कर्मचारियों से लेकर उच्च अधिकारियों की हिस्सेदारी निश्चित होती है। इसी लिए इन अवैध स्टैंडों पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हो रही है। जबकि इन अवैध स्टैंडों के कारण कस्बा के प्रमुख सड़कों पर दिन भर जाम लगने की गंभीर समस्या बनी रहती है। और इस जाम में फंसकर प्रतिदिन सैकड़ों स्कूली बच्चों, मरीजों,प्रशव पीड़िताओं और बीमार तथा दुर्घटना ग्रस्त लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इसके बाद भी स्थानीय पुलिस और प्रशासन यहां के अवैध आटो स्टैंड और बेतरतीब ई रिक्शा संचालकों पर पूरी तरह से मेहरबान बना हुआ है।

डकैती सहित युवती को अगवा करने पर कोर्ट के आदेश से रिपोर्ट दर्ज

कोंच(जालौन): कोर्ट के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोपियों ने घर में घुसकर डकैती की घटना को अंजाम दिया था और युवती को अगवा कर ले गए थे। पुलिस द्वारा रिपोर्ट नहीं लिखे जाने के बाद युवती के चाचा ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। आरोपी कुठौंद थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम ब्यौना निवासी रघुनंदन पुत्र उजागर ने न्यायालय में वाद दायर कर आरोप लगाया कि 8 सितंबर की दोपहर करीब एक बजे शैलेंद्र सिंह, भैयालाल, पप्पू, गोलू, शत्रुघ्न निवासीगण हुसेपुरा थाना कुठौंद व प्रमोद कुमार निवासी दौलतपुर थाना कुठौंद उसके घर में घुस आए थे और उसके माता-पिता के साथ मारपीट कर घर में रखे सामान में तोड़फोड़ की थी। इसके साथ ही अलमारी में रखी 50 हजार की नकदी तथा उसकी मां का मंगलसूत्र व अंगूठी जबरन लूट लिए थे एवं उसकी भतीजी को जबरन अपने साथ ले गए थे। कोर्ट के आदेश पर कोंच कोतवाली पुलिस ने बीएनएस की धारा 115(2), 333, 332, 324(4), 310(2) में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

डीएम ने गौशाला पहुंचकर पहनाए काऊ कोट

उरई(जालौन): जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने विकासखंड डकोर के ग्राम नुनसाई स्थित गौशाला का निरीक्षण कर गौवंश संरक्षण के प्रति प्रशासन की संवेदनशील प्रतिबद्धता का परिचय दिया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने ठंड से बचाव हेतु गौवंशों को काऊ कोट पहनाए तथा स्नेहपूर्वक गुड़ खिलाकर उनके स्वास्थ्य एवं पोषण की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने गौशाला में चारा, पेयजल, साफ-सफाई एवं ठंड से बचाव की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि गौवंशों की देखभाल में किसी प्रकार की लापरवाही न हो। उन्होंने कहा कि गौवंश संरक्षण शासन की प्राथमिकताओं में शामिल है और गौशालाओं में मानकों के अनुरूप सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। जिलाधिकारी ने गौशाला प्रबंधन समिति को निर्देश दिए कि नियमित निरीक्षण कर गौवंशों के स्वास्थ्य की निगरानी की जाए तथा शीतलहर के दृष्टिगत आवश्यक सभी इंतजाम समय से पूरे किए जाएं, ताकि गौवंश सुरक्षित एवं स्वस्थ रहें। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी केके सिंह, परियोजना निदेशक अखिलेश तिवारी, ग्राम कार्यक्रम अधिकारी शरद अवस्थी, ग्राम प्रधान आदि मौजूद रहे।

पोषण योजनाओं के अनुश्रवण में न बरती जाए शिथिलता

● **लाभार्थी से संवाद कर लक्ष्य पूर्ति के दिए निर्देश**

उरई(जालौन): जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला पोषण समिति/कन्वर्जेन्स विभाग की समीक्षा बैठक कर बाल विकास एवं पोषण से जुड़ी योजनाओं की गहन समीक्षा की। उन्होंने कहा कि शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं में किसी भी स्तर पर शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण लाभ सुनिश्चित किया जाए। आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों द्वारा पोषण ट्रैकर पर फीडिंग, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, एनआरसी में बच्चों का संदर्भन, आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण, मिशन कर्मयोगी तथा आंगनवाड़ी सहायिका भर्ती प्रक्रिया की विस्तृत समीक्षा इस दौरान की गई।

पोषण ट्रैकर पर लाभार्थियों के फेस कैप्चरिंग एवं ई-केवाईसी में खराब प्रगति पाए जाने पर सीडीपीओ माधौगढ़ एवं कुठौंद को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए जबकि फेस कैप्चरिंग के माध्यम से पोषाहार वितरण में लापरवाही पर सीडीपीओ कुठौंद व कदौरा को चेतावनी दी गई। जिलाधिकारी ने सभी सीडीपीओ व सुपरवाइजरों को निर्देशित किया कि वे नियमित रूप से आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करें और यह सुनिश्चित करें कि समस्त पात्र लाभार्थियों को बिना किसी अनियमितता के पोषाहार प्राप्त हो। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति कम पाए जाने पर प्रत्येक सप्ताह मॉनिटरिंग करने तथा 31 मार्च 2026 तक शत-प्रतिशत आवेदन कराने के निर्देश दिए गए। एनआरसी में दिसंबर 2025 में मात्र 9 बच्चों के भर्ती होने पर असंतोष व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि प्रत्येक परियोजना से कम से कम 2-2 बच्चों को एनआरसी में भर्ती कराया जाए। उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिला व ब्लॉक कोऑर्डिनेटरों को 26 जनवरी को प्रशस्ति पत्र प्रदान करने के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. देवेंद्र भिटौरिया, जिला विकास अधिकारी निशांत पांडेय, जिला पंचायती राज अधिकारी राम अयोध्या प्रसाद, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी चंद्रप्रकाश, जिला कार्यक्रम अधिकारी शरद अवस्थी सहित समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, मुख्य सेविकाएं, लिपिक एवं जिला/ब्लॉक कोऑर्डिनेटर उपस्थित रहे।

स्कॉर्पियो से लाई जा रही थी अवैध शराब, 40 पेटी के साथ 4 तस्कर दबोचे

● **पुलिस की सतर्कता से तस्करों की साजिश नाकाम, बुंदेलखंड में सप्लाई से पहले गिरफ्तारी**

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

उरई(जालौन): पुलिस ने शराब तस्करी के एक बड़े अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए चार शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने तस्करी के लिए लाई गई भारी मात्रा में मध्यप्रदेश निर्मित देशी शराब बरामद की है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 1 लाख 60 हजार रुपये बताई जा रही है।

पुलिस अधीक्षक डॉ दुर्गेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा करते हुए बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी मध्यप्रदेश में अवैध शराब का निर्माण कर उसे जालौन सहित बुंदेलखंड के विभिन्न जिलों में सप्लाई करने की योजना बना रहे थे। इसी सिलसिले में उक्त लोग शराब की खेप लेकर जालौन पहुंचे थे लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। यह कार्रवाई जालौन कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बंगरा रोड पर चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान की गई। चेकिंग के समय पुलिस को गुजरात नंबर की एक संदिग्ध स्कॉर्पियो गाड़ी आती दिखाई दी। वाहन को रोककर तलाशी ली गई तो उसमें से मध्यप्रदेश ब्रांड की 40 पेटी अवैध देशी शराब बरामद हुई। इन पेटियों में कुल 2000 क्वार्टर शराब पाई गई। पुलिस जांच में सामने आया कि पकड़े गए चारों तस्कर मध्यप्रदेश के भिंड और दतिया जिलों के निवासी हैं। ये आरोपी लंबे समय से अवैध शराब के कारोबार में लिप्त थे और सीमा से सटे जिलों का फायदा उठाकर उत्तर प्रदेश के जालौन व आसपास के इलाकों में शराब खपाने की फिराक में थे। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और सभी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। साथ ही तस्करी में प्रयुक्त स्कॉर्पियो वाहन को भी जब्त कर लिया गया है।

मामले की गहन जांच की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं तथा शराब कहां-कहां सप्लाई की जानी थी। पुलिस का कहना है कि जिले में अवैध शराब के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। शराब तस्करी न केवल कानून व्यवस्था के लिए चुनौती है, बल्कि इससे समाज में अपराध और दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ती है। ऐसे में पुलिस द्वारा की गई यह कार्रवाई शराब माफियाओं के लिए कड़ा संदेश है। पुलिस ने आम जनता से भी अपील की है कि यदि कहीं अवैध शराब का निर्माण, भंडारण या बिक्री होती दिखाई दे तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें।

बुढार स्टेडियम में सजेगा क्रिकेट का महाकुंभ

● **अखिल भारतीय विधायक गोल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट 13 जनवरी से, देशभर की टीमें लेंगी भाग**

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

(शहडोल)। खेल प्रेमियों के लिए बुढार नगर एक बार फिर क्रिकेट के रंग में रंगने जा रहा है। नगर के स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे मैदान में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला अखिल भारतीय विधायक गोल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट इस वर्ष भी पूरे शान-ओ-शौकत के साथ आयोजित किया जा रहा है। प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ 13 जनवरी को होगा, जबकि टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 21 जनवरी को खेला जाएगा। यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट न केवल क्षेत्रीय बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुका है। हर वर्ष की तरह इस बार भी देश के विभिन्न हिस्सों से आई मजबूत और अनुभवी टीमें मैदान में अपना दमखम दिखाएंगी। आयोजन को लेकर नगर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है।

युवाओं को खेलों से जोड़ने की अनूठी पहल

इस अखिल भारतीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन नगर की प्रतिष्ठित खेल एवं सामाजिक संस्था फ्रेंड्स स्पोर्ट्स एंड कल्चरल सोसाइटी के तत्वावधान में किया जा रहा है। आयोजकों के अनुसार टूर्नामेंट का मुख्य उद्देश्य युवाओं को खेलों के प्रति जागरूक करना, उन्हें सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाना और स्थानीय प्रतिभाओं को एक मजबूत मंच प्रदान करना है।

संस्था का मानना है कि खेल न केवल शारीरिक विकास का माध्यम है, बल्कि यह अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, टीम भावना और आत्मविश्वास भी विकसित करता है। इस प्रतियोगिता के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के प्रतिभाशाली खिलाड़ी अपने खेल कौशल का प्रदर्शन कर आगे के बड़े मंचों तक पहुंच सकते हैं।

भव्य होगा उद्घाटन समारोह

टूर्नामेंट का उद्घाटन समारोह बेहद भव्य और यादगार बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। उद्घाटन अवसर पर नगर एवं जिले के कई जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, खेल संघों के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में खेल प्रेमी नागरिक मौजूद रहेंगे। स्थानीय विधायक जय सिंह मरावी के मार्गदर्शन में आयोजित होने वाला यह टूर्नामेंट शहर ही नहीं बल्कि पूरे संभाग में अपनी लोकप्रियता के लिए जाना जाता है। उद्घाटन समारोह में खिलाड़ियों का परिचय, अतिथियों का स्वागत, खेल भावना को समर्पित संदेश और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी देखने को मिल सकती हैं।

देशभर की टीमें लेंगी भाग

आयोजन समिति के सक्रिय सदस्य अवधेश पांडे (पिंटू) ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार टूर्नामेंट में स्थानीय टीमों के साथ-साथ देश के कई प्रमुख क्रिकेट केंद्रों की टीमें हिस्सा लेंगी। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाली प्रमुख टीमें निम्नलिखित शहरों से होंगी। जिसमें दिल्ली, बिलासपुर, जबलपुर, प्रयागराज, रीवा, शहडोल, अंबिकापुर, पेंड्रा, उमरिया और बुढार की टीमें शामिल है। इन टीमों में कई ऐसे खिलाड़ी शामिल हैं जो राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर चुके हैं। इससे टूर्नामेंट का स्तर और रोमांच दोनों ही और अधिक बढ़ने की उम्मीद है।

T20 प्रारूप में होंगे मुकाबले

टूर्नामेंट का प्रारूप T20 रखा गया है, जो वर्तमान समय में क्रिकेट प्रेमियों के बीच सबसे लोकप्रिय फॉर्मेट माना जाता है। प्रतियोगिता की खास बात यह होगी कि प्रत्येक दिन एक मैच खेला जाएगा,सभी मुकाबले नॉकआउट आधार पर होंगे,हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। यह प्रारूप खिलाड़ियों में प्रतिस्पर्धात्मक भावना को बढ़ावा देता है और दर्शकों के लिए भी रोमांच से भरपूर रहता है। आयोजकों का कहना है कि इस प्रणाली से सभी टीमों को बराबर अवसर मिलेगा और हर मैच फाइनल जैसा रोमांच पैदा करेगा।

मैदान और सुविधाओं की व्यापक व्यवस्था

स्थानीय स्व. कुशाभाऊ ठाकरे मैदान को पूरी तरह से सजाया-संवारा जा रहा है। मैदान की पिच और आउटफील्ड को उच्च गुणवत्ता के अनुरूप तैयार किया जा रहा है, ताकि खिलाड़ियों को बेहतर खेल का अनुभव मिल सके। इसके साथ ही दर्शकों और खिलाड़ियों की सुविधा के लिए बैठने की समुचित व्यवस्था, पेयजल की उपलब्धता, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा, प्रकाश व्यवस्था

स्वच्छता और साफ-सफाई

जैसी आवश्यक सुविधाएं भी सुनिश्चित की जा रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन का भी पूरा सहयोग लिया जा रहा है, ताकि आयोजन शांतिपूर्ण और सफल रूप से संपन्न हो सके।

आकर्षक पुरस्कार और सम्मान

टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाली टीमों और खिलाड़ियों के लिए आकर्षक पुरस्कारों की व्यवस्था की गई है। आयोजकों के अनुसार विजेता टीम को भव्य ट्रॉफी और नकद पुरस्कार उपविजेता टीम को ट्रॉफी एवं नकद इनाम सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीमों को भी विशेष सम्मान प्रदान किया जाएगा।

इसके अलावा व्यक्तिगत प्रदर्शन के आधार पर मैन ऑफ द मैच,बेस्ट बैट्समैन,बेस्ट बॉलर,बेस्ट ऑलराउंडर जैसी श्रेणियों में भी खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा, जिससे खिलाड़ियों का मनोबल और अधिक बढ़ेगा।

स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मिलेगा लाभ

इस तरह के बड़े खेल आयोजनों से केवल खेल संस्कृति ही नहीं, बल्कि स्थानीय व्यापार और अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलता है। टूर्नामेंट के दौरान बुढार नगर में बाहरी टीमों और दर्शकों की आवाजाही बढ़ेगी, जिससे होटल, दुकानदार, परिवहन और छोटे व्यापारियों को भी आर्थिक फायदा होगा।

खेल प्रेमियों में भारी उत्साह

टूर्नामेंट को लेकर नगर और आसपास के क्षेत्रों में जबरदस्त उत्साह का माहौल है। क्रिकेट प्रेमी लंबे समय से इस प्रतियोगिता का इंतजार कर रहे थे। आयोजन समिति ने नगरवासियों और खेल प्रेमियों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में स्टेडियम पहुंचकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करें और खेल भावना को बढ़ावा दें।

खेल से जुड़ेगा बुढार, बनेगा पहचान का केंद्र

अखिल भारतीय विधायक गोल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट ने बुढार को खेल के नक्शे पर एक नई पहचान दिलाई है। यह आयोजन न केवल खिलाड़ियों को मंच देता है, बल्कि युवाओं को नशे और नकारात्मक गतिविधियों से दूर रखकर खेलों की ओर प्रेरित करता है। आने वाले दिनों में जब पहली गेंद फेंकी जाएगी और चौकों-छक्कों की गूंज स्टेडियम में सुनाई देगी, तब बुढार वास्तव में क्रिकेट के महाकुंभ का साक्षी बनेगा।

सरस्वती शिशु मंदिर/शिशु वाटिका में संपन्न हुआ सप्तशक्ति संगम कार्यक्रम

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

कोंच(जालौन): अच्छे और सशक्त समाज के निर्माण के लिए स्त्री और पुरुष की समान भूमिका आवश्यक है। जब तक महिलाओं को समान अवसर और सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक समाज का समुचित विकास संभव नहीं हो सकता। यह बात सरस्वती शिशु मंदिर/शिशु वाटिका मंडी परिसर कोंच में आयोजित सप्तशक्ति संगम कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए गीता देवी स्वर्णकार ने कही।

विद्या भारती के निर्देश पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व नगर पालिका चेयरपर्सन विनीता सीरौठिया रहीं। मुख्य वक्ता के रूप में सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जालौन की प्रधानाचार्या आनंदीबाई हर्षे, जिला संयोजिका सप्तशक्ति संगम सुनीता शर्मा तथा क्षेत्रीय बालिका शिक्षा प्रमुख पूर्वी उत्तर प्रदेश अर्चना अवस्थी ने अपने विचार रखे। विशिष्ट अतिथि के रूप में संतोषी सिंह, मधु गुप्ता, कृष्णा झा, मीना गुप्ता व किरण बुधौलिया बालिका विद्या मंदिर उरई मंचासीन रहीं। विद्यालय की प्रधानाचार्या आभा तिवारी ने अतिथियों का परिचय कराया। कार्यक्रम संयोजिका साधना व निवेदिता ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। वक्ताओं ने अपने उद्बोधन में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती और अहिल्याबाई होल्कर के जीवन से प्रेरणा लेते हुए महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान घरेलू जिम्मेदारियों के साथ समाज और परिवार में उल्लेखनीय योगदान देने वाली महिलाओं रेखा गिरवासिया, रन्नो देवी, राजकुमारी सोनी,

नंदिनी कुशवाहा और निधि सिंघल को विद्यालय की ओर से सम्मानित किया गया। सभी उपस्थित महिलाओं का पट्टिकाएं पहनाकर स्वागत किया गया। संचालन साधना ने किया। इस दौरान अंजना, चंदा, दीक्षा, आकांक्षा, सरिता, निवेदिता, रंजना, सरला, शिवानी, वंदना, तान्या व्यास, प्रभा गुप्ता सहित अभिभावक व महिलाएं मौजूद रहीं।

ऑपरेशन कन्विक्शन में पुलिस को बड़ी सफलता, आर्म्स एक्ट मामले में आरोपी को 2 साल की सजा

उरई(जालौन): पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। प्रभावी विवेचना, सशक्त साक्ष्य संकलन और सटीक पैरवी के चलते एक आपराधिक मामले में आरोपी को न्यायालय से सजा दिलाई गई है। पुलिस अधीक्षक डॉ दुर्गेश कुमार के निर्देशन तथा संबंधित थाना प्रभारी, डीजीसी (क्रिमिनल) और कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी से न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराया है। मामले में न्यायालय द्वारा आरोपी को दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी फारुख खां पुत्र मुस्तफा निवासी ग्राम कुकुरगांव कोतवाली उरई के कब्जे से दुनाली बंदूक के चार जिंदा कारतूस बरामद किए गए थे। इस संबंध में 3 मार्च 2013 को कोतवाली उरई में धारा 41 भादवि एवं 3/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य

संकलित किए गए तथा गवाहों के बयान दर्ज कर दिनांक 26 अप्रैल 2013 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। इसके बाद अभियोजन पक्ष द्वारा निरंतर प्रभावी पैरवी की गई।

सड़क चौड़ीकरण को लेकर गरजा बुलडोजर

अंबेडकर चौराहे से मंशापूर्ण मंदिर तक चला अतिक्रमण हटाओ अभियान

उरई (जालौन): शहर में सड़क चौड़ीकरण कार्य को लेकर प्रशासन का सख्त रुख देखने को मिला। जिलाधिकारी के निर्देश पर सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में नगर पालिका और पुलिस की संयुक्त टीम ने सड़क किनारे पसारे गए अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्यवाही की। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत सड़क और फुटपाथ पर सामान रखकर कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने बुलडोजर की मदद से सड़क किनारे रखे सामान, अस्थायी ढांचे और दुकानों को हटाकर ध्वस्त करने में देरी नहीं की। अधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि सरकारी भूमि पर दोबारा अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह अभियान नगरपालिका क्षेत्र में अंबेडकर चौराहे से मंशापूर्ण मंदिर तक चलाया गया है। प्रशासन की इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है जबकि स्थानीय लोगों ने सड़क चौड़ीकरण और यातायात सुगमता के लिए इसे आवश्यक कदम बताया है।

मौदहा के परसदवा डेरा पहुंचे राजस्व व पीडब्ल्यूडी के अधिकारी

बीते तीन दिनों से सड़क की मांग को लेकर सड़क और बैठे हैं ग्रामीण

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

हमीरपुरः– मौदहा विकास खण्ड के गऊघाट छानी से जुड़े मजरा परसदवा डेरा में संपर्क मार्ग निर्माण के लिए शुरू हुआ अनशन दूसरे दिन बुधवार को भी जारी रहा है। तीसरे दिन अनशन स्थल पर पहुंचे राजस्व एवं लोकनिर्माण विभाग के अधिकारियों ने अपने तर्क दिए लेकिन डेरा के लोगों ने निर्माण कार्य शुरू होने तक अनशन जारी रखने की बात कही है। ज्ञात हो कि मौदहा विकास खण्ड के गांव छानी गउघाट के मजरा परसदवा डेरा के लोग सड़क निर्माण की मांग को लेकर सोमवार से अनशन पर बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि आजादी से लेकर आज तक उनके डेरा में आने जाने के लिए सड़क निर्माण नहीं कराया गया है। जिससे कि यहां के लोगों को गंभीर मुसीबतों का सामना करना पड़ता है।बारिश के दिनों में बस्ती के चारों ओर दल-दल नज़र आता है। सड़क न होने से इस डेरा का संपर्क आसपास के गांवों तथा तहसील एवं जिला मुख्यालय से पूरी तरह टूट जाता है। डेरा में आने जाने के लिए बैलगाड़ी ही एक मात्र सहारा रहता है। इस गंभीर समस्या के चलते इन्होंने दर्जनों बार उच्च अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों से सड़क की मांग की है लेकिन आज तक किसी ने भी ध्यान नहीं दिया है। सड़क न होने से सबसे गंभीर समस्या बीमार लोगों और प्रशव पीड़िताओं को उठानी पड़ती है। समय से अस्पताल न पहुंचने के कारण इन्हें दुखद हादसों का शिकार होना पड़ता है। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के सभी दावे हवा हवाई साबित हो रहे हैं। डेरा वासियों का कहना है कि उन्होंने सड़क निर्माण की मांग को लेकर एक सप्ताह पूर्व जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा था लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ है। ऐसे में अनशन व धरना प्रदर्शन करना ही एक मात्र रास्ता बचा है। सड़क का निर्माण कार्य शुरू होने तक यह आंदोलन जारी रहेगा। हालांकि बुधवार को आंदोलन स्थल पर पहुंचे नायब तहसीलदार सत्यप्रकाश वर्मा और लोकनिर्माण विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर ए के सिंह ने सड़क निर्माण से संबंधित अपने तमाम तर्क देकर अनशन कारियों को समझाते बुझाने का प्रयास किया है लेकिन अनशन कारियों का कहना है कि सड़क की मांग को लेकर उनका आंदोलन तबतक चलेगा जबतक कि निर्माण कार्य शुरू नहीं हो जाता है बुधवार को अनशन में राजेंद्र निषाद, केशना निषाद, रामकुमार पाल, रामदास, दनकू, शिवगुलाम, छोटेलाल, अरविंद, भैयालाल पाल, उदित, नारायण, रामदुलारी, मुन्नी, मनकी, रेखा, संपत, किशोरी, गयादीन, नरेश, सुनील, श्यामू, धीरज, बसंत, रामोतार, चुन्नू यादव, जगरानी, समलिया सहित लगभग दो दर्जन लोग मौजूद रहे हैं।